जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 101 प्रभात चूरू, गुरूवार 7 अगस्त, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कराने के लिए स्पीकर के ओएसडी सुप्रीम कोर्ट जायेंगे?

दूसरी ओर, एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दर्ज कराने वाले प्रार्थी शेखर मेवाड़ा व कैलाश राम ने सुप्रीम कोर्ट में ''केविएट'' फाइल की, 5 अगस्त को इस मामले में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6, अगस्त। एक अहम घटनाक्रम में, अब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट और न्यायाधीश समीर जैन ने 4 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था।

इससे भी ज्यादा चौंकाने और स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा को ओम बिड़ला ने दिल्ली बुलाया था, जहां उन्होंने बिड़ला और राजीव दत्ता, दोनों से मुलाकात की।

संभवत: यह पहला अवसर है, जब किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उस आरोपी से मुलाकात की है, जिसके खिलाफ राज्य के हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया हो।

- जैसा कि विदित ही है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश समीर जैन ने, लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ 'ह्यूमन ट्रैफिकिंग'' के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश चार अगस्त को पारित किये थे।
- अजीबोगरीब बात यह भी है कि कांग्रेस ने भी किन्हीं कारणों से इस प्रकरण में चुप्पी साधने का निर्णय सा ले लिया है। क्योंकि, जब किसी कनिष्ठ कर्मचारी ने इस मामले की खबर, पीसीसी की वैबसाइट पर डाली तो तुरन्त आदेश आ गया, पार्टी के उच्चतम स्तर से, कि प्रकरण की स्टोरी वैबसाइट पर नहीं दिखाई जाए।

हालांकि मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, यह केवल कयास ही है, लेकिन पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों में इस बात को लेकर खासी चर्चा और उत्सुकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने डीजीपी को क्या निर्देश दिए होंगे।

सूत्रों के अनुसार, कथित रूप से मानव तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे राजीव दत्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के आदेश को रद्द कराया जा सके। इसके लिए वे एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं, शेखर मेवाड़ा और कैलाश राम ने, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तथा गड़बड़ी की आशंका के कारण पहले ही, 5 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, ताकि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला न हो सके।

राजस्थान और दिल्ली की सत्ता के गलियारों में दत्ता के इस मामले को लेकर काफी चर्चा और दिलचस्पी देखी-सुनी जा रही है।

दिलचस्प बात यह है कि किसी भी कांग्रेस नेता ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी

जयपुर, 6 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने मामले में प्रति-जवाब पेश करने के लिए याचिकाकर्ता को 8 अगस्त का समय दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने ये आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- याचिकाकर्ता 8 अगस्त को प्रति जवाब पेश करेंगे।

ईडी की ओर से याचिकाकर्ता की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रकरण में एसीबी की ओर से दर्ज अन्य एफआईआर में याचिकाकर्ता की भूमिका को बताया गया है। वहीं, याचिकाकर्ता के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि को लौटाना भी बताया जा रहा है, तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने विभाग की टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत प्राप्त की है। इसके अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत आरोपी को उस समय ही जमानत दी जा सकती है, जब अदालत इस बात से प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि वह इस अपराध का दोषी नहीं है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने भारत पर रूस से ''ऑयल'' खरीदने के एवज़ में 25 प्रतिशत टैरिफ और लगाया

अमेरिका ने ऐसी पैनल्टी चीन पर लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई, हालांकि, चीन भी भारी मात्रा में रूस से ''ऑयल'' खरीदता है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

वॉशिंगटन, 6, अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात पर आज 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ (शुल्क) लागू कर दी है, जिसकी उन्होंने पहले ही धमकी दी थी। यह नया टैरिफ पहले से लगे 25 प्रतिशत के ''रैसिप्रोकल टैरिफ'' (प्रतिशोधी शुल्क) के ऊपर जोड़ा जाएगा, जिससे कुल शुल्क अगले 21 दिनों में 50 प्रतिशत हो जाएगा।

इस नए कदम के साथ ही, ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर पहला ''सेकन्डरी सैंक्शन'' लगा दिया है, जबकि रूस के तेल के दूसरे बड़े खरीदार चीन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

इस संयुक्त शुल्क से भारत एक विशेष स्थिति में आ जाएगा, जिसमें उस पर अमेरिका का सबसे ऊंचा 50 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसका सीधा असर यह हो सकता है कि भारतीय निर्यात पूरी तरह से अमेरिकी बाज़ार से बाहर हो जाए, क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी।

- इस बढ़े हुए टैरिफ के कारण भारतीय माल अमेरिका के बाज़ारों से लुप्त ही हो जाएगा तथा भारत को अन्य मार्केट ढूंढ़ने पड़ेंगे, अपना माल बेचने के लिए।
- पर, रूस के अलावा अन्य स्रोतों से ऑयल खरीदने का विकल्प नहीं बचा है भारत के समक्ष। क्योंकि, अन्य स्रोतों से ऑयल की खरीद बहुत महँगी पड़ेगी भारत को।
- भारत का अमेरिका को निर्यात बहुत कम है तथा निर्यात बंद होने से इतना नुकसान नहीं होगा, जितना ''ओपन मार्केट'' से ऑयल खरीदने से होगा।
- चीन पर पैनल्टी नहीं लगाने से ट्रंप की ''टी.ए.सी.ओ.'' (ट्रंप आलवेज़ चिकन्स आउट) की छवि को और स्पष्ट और मजबूत कर देता है।

ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब अमेरिका की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत चल रही है। ट्रंप रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वे जल्दी से यूक्रेन में अपना युद्ध समाप्त करें।

चाहे अनचाहे, इस कदम ने भारत को अमेरिका और रूस जैसी प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियों के बीच चल रही भू-राजनीतिक खींचतान के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है, जो यूक्रेन युद्ध को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ रणनीतिक दांव-पेंच खेल रहे हैं। भारत ने ट्रंप की भारतीय निर्यात पर सेकन्डरी प्रतिबंध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने संसदीय गतिरोध खत्म करने का समाधान दिया सरकार को

विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बजाय चुनाव सुधार पर चर्चा करवाने की पेशकश की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। एक रचनात्मक पहल करते हुए, विपक्ष ने कथित रुप से पीठासीन अधिकारी और सत्तापक्ष को ''मध्य मार्ग'' के रुप में एक सुझाव दिया है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पैशल इन्टैन्सिव सिविज़न/एस.आई.आर.) पर बहस की मांग को लेकर संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए ''चुनावी सुधारों'' पर चर्चा कराई जाए।

हालाँकि, सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विपक्षी दलों के सूत्रों का कहना है कि सरकार इस तरह की किसी भी बहस की अनुमति देने के मूड में नहीं है।

बुधवार को लोकसभा में एस.आई.आर. पर चर्चा की मांग के दौरान केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा के नियम विचाराधीन (सब- जूडिस) मामलों पर चर्चा की अनुमति नहीं देते। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।

- लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि संसद में किन-किन वर्षों में चुनाव सुधार पर चर्चा हुई है।
- केन्द्र सरकार ने विपक्ष के प्रस्ताव पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विपक्षी दलों के सूत्रों ने कहा कि ऐसा लगता है, सरकार चुनाव सुधार पर चर्चा कराने की इच्छुक भी नहीं है।

इस बीच, कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई की एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया कि संसद में चुनावी सुधारों और चुनाव आयोग के कामकाज पर चर्चा का एक लंबा इतिहास रहा है।

रमेश ने कहा कि गोगोई ने गहन शोध किया है और ''मोदी सरकार के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत यहां बने केन्द्रीय सचिवालय भवनों में से एक कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उनके साथ केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी थे। इस दौरान मोदी ने कर्तव्य भवन का दौरा किया और यहां बनायी गयी सभी सुविधाओं का निरीक्षण भी किया।

- 50 हजार वर्ग मीटर में फैला यह भवन पूर्णतया ईकोफ्रैंडली है, और कई प्रमुख मंत्रालयों के कार्यालय इसी भवन में बनाए जाएंगे।

यह लगभग एक लाख 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है, जिसमें दो बेसमेंट और सात तल (भूतल 6 तल) हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय विभाग और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उत्तरकाशी आपदा में 100 से अधिक के मरने की आशंका

आधी रात के बाद बादल फटने से आई बाढ़ से भारी विनाश हुआ कई गांव शेष दुनिया से कट गए हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली कस्बे के पास सोमवार देर रात बादल फटने से आई भीषण बाढ़ में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस आपदा ने भारी तबाही मचाई है, कई इलाके पूरी तरह से कट गए हैं, क्योंकि सड़कों के ध्वस्त हो जाने, पुलों के टूटने और संचार लाइनों के बाधित होने से संपर्क टूट गया है।

आपदा के 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद, राहत एवं बचाव कार्यों में गंभीर अड़चनें बनी हुई हैं। राहत कार्यों में प्रशासन के सहयोग के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया है, लेकिन दुर्गम इलाकों तक पहुंच अब भी सीमित है। जमीनी रिपोर्टों के अनुसार, महत्वपूर्ण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, राजमार्ग के कम से कम तीन बड़े

- गंगोत्री नेशनल हाईवे को भारी नुकसान हुआ है। धराली से 40 किलोमीटर दूर भटवाड़ी के पास ही बैरिकेड लगाकर हाईवे को बंद कर दिया गया है।
- राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए विमानों से राहत सामग्री गिराई, क्योंकि खराब मौसम और भारी विनाश के कारण राहत व बचाव दल आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

हिस्से धंस चुके हैं या टूट चुके हैं, जबकि कई अन्य हिस्से भूस्खलन के कारण बह गए हैं। फिलहाल यह हाईवे धराली से लगभग 40 किलोमीटर पहले भटवाड़ी के पास बैरिकेड लगा दिए गए हैं।

क्षेत्र में बिजली आपूर्ति, मोबाइल नेटवर्क और अन्य आवश्यक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इनकी बहाली के प्रयास जारी हैं, लेकिन भारी तबाही और लगातार खराब मौसम के चलते प्रगति धीमी है। गंगनानी के पास एक पुल पूरी तरह से बह गया है, जिससे प्रभावित इलाका और अधिक अलग-थलग पड़ गया है

राज्य सरकार ने हवाई राहत अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हेलीकॉप्टरों से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए और प्रभावित लोगों के लिये आवश्यक सामग्री गिरायी जा रही है। मलबे से एक और शव मिलने के बाद, अब तक आधिकारिक तौर पर केवल पाँच मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और निवासियों को आशंका है कि मौतों का वास्तविक आंकड़ा कहीं अधिक हो सकता है। जमीन पर काम कर रही राहत टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, नुकसान का जायज़ा लिया और पूर्ण सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हर एक जीवन कीमती है और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हालात का जायज़ा लिया और मुख्यमंत्री धामी से सीधे बात कर संकटपूर्ण स्थिति की जानकारी और सरकारी प्रयासों और उपायों के बारे में अपडेट लिया।

धराली तक वैकल्पिक मार्ग खोलने के प्रयास जारी हैं, लेकिन सड़क

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकी गई

नैनीताल, 06 अगस्त। उत्तराखंड के कुमाऊं में बादल फटने का कहर फिलहाल बुधवार शाम को थम गया, लेकिन उसका असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बुधवार को धारचूला से आगे नहीं बढ़ पाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैलाश मानसरोवर यात्रा का 48 सदस्यीय चौथा दल मंगलवार को पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंच गया था। रात्रि विश्राम के बाद, आज दल को उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित पहले आधार शिविर गुंजी पहुंचना था, लेकिन अतिवृष्टि के चलते भूस्खलन होने से धारचूला-लिपुलेख मार्ग कई जगह अवरुद्ध हो गया।

- उत्तराखंड में आई आपदा की वजह से यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

एस.सी.ओ. सम्मेलन में प्र.मंत्री मोदी जायेंगे इस माह

भारत की कूटनीति के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि भारत ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहता, कि दोनों ''सुपर पावर'' ग्रुप में से एक-एक का चयन करना पड़े उसे

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने के अंत में चीन जा रहे हैं, जहाँ वे शंघाई कोऑपरेशन आर्गनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और भारत प्रमुख शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के बीच फंसा हुआ है। इस यात्रा की पृष्ठभूमि विशेष रूप से जटिल है, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाते हुए भारत पर भारी शुल्क लगाए हैं, साथ ही भारत पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव भी बना रहे हैं, जबकि रूस, भारत का लंबे समय से रणनीतिक साझेदार रहा है। इन घटनाओं ने भारत की कूटनीतिक गुंजाइश को सीमित कर दिया है, जिससे नई दिल्ली के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में विविधता लाना आवश्यक हो गया है।

इस पृष्ठभूमि में, मोदी की चीन पहल को एक रणनीतिक पुनर्संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसा कूटनीतिक दांव, जो अमेरिकी दबाव को कम करने में सहायक हो सकता है। भारत भले ही वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध हो, विशेषकर प्रौद्योगिकी, रक्षा और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढांचे में, लेकिन बीजिंग के साथ नए सिरे से संवाद एक अधिक संतुलित विदेश नीति का संकेत देता है, जो रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत प्रतिद्वंद्वी वैश्विक शक्तियों के बीच किसी एक पक्ष का चयन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

- भारत, अमेरिका के साथ टैक्नॉलजी, डिफैंस सहयोग तो चाहता है, पर, क्षेत्रीय मामलों में अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता की इच्छा भी रखता है।
- साथ ही पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किये गये नरसंहार वाकिया भी ताज़ा है, भारत के दिलो-दिमाग पर। अत:, चीन द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेना हर मामले में, चाहे वह मामला आतंकवादी गतिविधियों के बारे में ही क्यों न हो, भारत के लिए पीड़ादायक अहसास है।
- एस.सी.ओ. सम्मेलन में वॉशिंगटन, मॉस्को व बीजिंग के बीच कैसे संतुलन बैठाकर आगे बढा जाए, यह भारत के लिए वाकई में चुनौती है।
- चर्चा है कि सम्मेलन के दौरान प्र.मंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन व चीन के प्रैसिडैन्ट शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं।

हालांकि, यह संवाद कई जटिलताओं से भरा हुआ है। यह यात्रा उस समय हो रही है, जब कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में कई भारतीय सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की जान चली गई। इस घटना ने पाकिस्तान के प्रति चीन के रुख को लेकर भारत की चिंताओं को फिर से उभार दिया है, विशेष रूप से इस बात को लेकर कि चीन अब भी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने से हिचकता है। बीजिंग का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक मंचों पर बार-बार पाकिस्तान का बचाव करना, भारत और चीन के बीच तनाव का प्रमुख कारण रहा है।

ऐसे में, चीन के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारत की उच्चस्तरीय बैठकें केवल आर्थिक या सीमा-सम्बंधी कूटनीति तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि यह दोनों देशों के परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन साधने की एक चुनौतीपूर्ण कवायद होगी। क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को आर्थिक साझेदारी और एशिया में रणनीतिक प्रभाव बनाए रखने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक अक्टूबर से बहाल होंगी एयर इंडिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

नई दिल्ली, 06 अगस्त। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया के विमानों का परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, हालांकि अब धीरे-धीरे एयर इंडिया के विमानों की आवाजाही सामान्य होती जा रही है। इस बीच बुधवार को एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने

- अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सुरक्षा जांच लंबित होने की वजह से एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सेवा पर आंशिक रोक लगा दी गई थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

शहरों की बिगड़ती आबोहवा, नागरिकों का स्वास्थ्य ख़तरे में

राजस्थान एक गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। वायु, जल, ध्वनि और औद्योगिक प्रदूषण के साथ-साथ खनन से उत्पन्न धूल ने न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता को प्रभावित किया है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डाला है। शहरों की बिगड़ती आबोहवा ने सांस लेने में तकलीफ, बीमारियों में वृद्धि और पर्यावरणीय असंतुलन का गम्भीर संकट खड़ा कर दिया है। आज यह संकट केवल बड़े शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदूषण का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। राजस्थान के शहरों में वायु, जल, ध्वनि, औद्योगिक और खनन से संबंधित प्रदूषणों के कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आज वायु प्रदूषण राजस्थान के शहरों में एक गंभीर समस्या बन चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, श्रीगंगानगर, जयपुर, दौसा, कोटा और भिवाड़ी जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब और बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अप्रैल 2025 में श्रीगंगानगर में एक्यूआई 321 तक पहुंच गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों से कई गुना अधिक है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों की बढ़ती संख्या, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियां और खनन से उत्पन्न धूल शामिल हैं। जयपुर, जो पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है, में यातायात का दबाव और सड़कों पर उड़ने वाली धूल के कारण पीएम 10 और पीएम 2.5 जैसे महीन कणों की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। ये कण फेफड़ों में प्रवेश कर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) को बढ़ावा दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से भिवाड़ी, अलवर और कोटा में, कारखानों से निकलने वाला धुआं और रसायन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्त्रोत हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के एक अध्ययन के अनुसार, राजस्थान के शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे गैसीय प्रदूषकों का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे एक बहु-प्रदूषक संकट उभर रहा है। भिवाड़ी, जो एक औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है, में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत गैर-प्राप्ति वाले शहरों में शामिल है। राजस्थान के छोटे शहरों और कस्बों में भी वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट देखी जा रही है, जो पहले केवल बड़े शहरों तक सीमित थी। निर्माण गतिविधियां, सड़कों की मरम्मत और बुनियादी ढांचे के विकास ने भी धूल प्रदूषण के स्तर को की गुना बढ़ा दिया है। विशेष रूप से शुष्क जलवायु और तेज हवाओं के कारण धूल के कण हवा में लंबे समय तक रहते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता और खराब होती है।

वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह पर्यावरणीय संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसके अलावा, वायु प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग पर भी असर डाला है। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलें, जो कभी अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, अब प्रदूषण के कारण अपनी चमक खोती जा रही हैं। राजस्थान सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके कारण इसे किसी न किसी रूप से विफल माना ही जाएगा। राज्य में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर, विशेष रूप से हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और धौलपुर जैसे जिलों में, जहां 300 से ऊपर पहुंच गया है, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआं, और पराली जलाना प्रदूषण के प्रमुख स्त्रोत हैं। सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (९ँइ) के तहत कदम उठाए हैं, जैसे पराली जलाने पर रोक और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, लेकिन इनका प्रभाव बहुत सीमित रहा है।प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निगरानी में कमी, औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती का अभाव, और पुराने वाहनों पर नियंत्रण की कमी ने समस्या को और गंभीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान सहित अन्य राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर जवाब मांगा है। यह सरकार की निष्क्रियता को तो दर्शाता ही है जनजागरूकता और स्थानीय निकायों के सहयोग की कमी भी एक बड़ी बाधा है। हालांकि, हाल के प्रयासों में राजस्थान पुलिस को पराली जलाने पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए और सख्त नीतियों, नियमित निगरानी, और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देना आवश्यक है।

इसी जल प्रदूषण राजस्थान में एक और गंभीर चुनौती है। राज्य में जल संसाधनों की कमी पहले से ही एक बड़ी समस्या है, और उस पर जल प्रदूषण ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज और कृषि अपवाह ने नदियों, झीलों और भूजल को दूषित कर दिया है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक कचरे के कारण कई गांवों में पानी की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। एक ट्वीट में जोधपुर के अराबा, डोली और धवा जैसे गांवों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक कचरे के प्रभाव का जिक्र किया गया, जहां पानी इतना दूषित हो चुका है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। राज्य की प्रमुख नदियों, जैसे चंबल और बनास, में औद्योगिक और घरेलू कचरे का अंधाधुंध निपटान हो रहा है। कोटा और बूंदी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जिसमें भारी धातुएं जैसे सीसा, कैडमियम और आर्सेनिक शामिल हैं, नदियों में छोड़ दिया जाता है। ये धातुएं जलीय जीवन को नष्ट करने के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रही हैं। खतरनाक कचरा अधिकांशतः नदियों और जलाशयों में बहा दिया जाता है जो राजस्थान के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यहां जल संसाधनों की कमी के कारण लोग पहले से ही सीमित जल स्त्रोतों पर निर्भर हैं।

आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लगेगी।

भूजल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। कई क्षेत्रों में भूजल में नाइट्रेट, फ्लोराइड और भारी धातुओं की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण भूजल में धूल और रासायनिक अवशेषों का मिश्रण हो रहा है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में अनुपचारित सीवेज का रिसाव भूजल को और दूषित कर रहा है। यह स्थिति न केवल पीने के पानी की कमी को बढ़ा रही है, बल्कि जलजनित बीमारियों जैसे डायरिया, हैजा और टाइफाइड के मामलों में भी वृद्धि कर रही है। उदयपुर की फतेहसागर और रंगसागर झीलें, जो कभी शहर की शान थीं, अब सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण दूषित हो रही हैं। ध्वनि प्रदूषण के मामलों में तो राजस्थान के शहरों में खतरा और भी तेजी से उभरा है। जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों में वाहनों, कारखानों, लाउडस्पीकरों और निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न शोर ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। विशेष रूप से त्योहारों और सामाजिक आयोजनों के दौरान लाउडस्पीकरों और पटाखों का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को और बढ़ाता है। ग्राामीण क्षेत्रों में भी, खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण मशीनों और विस्फोटों की आवाज ने शांत वातावरण को नष्ट कर दिया है। खनन गतिविधियां राजस्थान में प्रदूषण का एक प्रमुख स्त्रोत हैं। राज्य में मार्बल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और अन्य खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन होता है, जिससे धूल और मलबे का उत्सर्जन होता है। उदयपुर, मकराना और राजसमंद जैसे क्षेत्रों में खनन से उत्पन्न धूल ने हवा और पानी दोनों को दूषित किया है। यह धूल न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाती है, बल्कि फसलों और मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित करती है। खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं, जो सिलिका धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है। इसके अलावा, खनन से उत्पन्न मलबा नदियों और जलाशयों में बह जाता है, जिससे जल प्रदूषण और बाढ़ का खतरा बढ़ता है।

औद्योगिक प्रदूषण भी राजस्थान के पर्यावरण को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भिवाड़ी, अलवर, कोटा और जोधपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला धुआं और रासायनिक कचरा न केवल हवा और पानी को दूषित कर रहा है, बल्कि मिट्टी को भी प्रभावित कर रहा है। जोधपुर में टेक्सटाइल उद्योगों से निकलने वाला रंगीन अपशिष्ट जल नदियों और भूजल में मिल रहा है, जिससे आसपास के गांवों में पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। कचरे का प्रबंधन तो एक बड़ी चुनौती है ही। शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे का ढेर और उसका अनुचित निपटान पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। जयपुर और कोटा जैसे शहरों में कचरे के ढेर खुले में जलाए जाते हैं, जिससे हवा में जहरीले धुएं का उत्सर्जन होता है। प्रदूषण का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी असर डाल रहा है। प्रदूषित हवा और पानी के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई है, जिससे चिकित्सा खर्च बढ़ा है। सिलिकोसिस, कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित किया है।

हालांकि प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत राजस्थान के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छ ईंधन, जैसे सीएनजी और एलपीजी, को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम स्थापित किए गए हैं, और कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। लेकिन इन नियमों का अनुपालन और कार्यान्वयन अभी भी अपर्याप्त है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए, सरकार ने नदियों और जलाशयों की सफाई के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। चंबल नदी की सफाई के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज के निरंतर निर्वहन ने इन प्रयासों को प्रभावित किया है। भूजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, कुछ शहरों में लाउडस्पीकरों और वाहनों के हॉर्न पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इन नियमों का पालन कम ही देखा जाता है। खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने कुछ क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण यह समस्या बनी हुई है। कचरे के प्रबंधन के लिए, कुछ शहरों में रीसाइक्लिंग और कम्पोस्टिंग सुविधाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ये प्रयास अभी प्रारंभिक चरण में हैं।

प्रदूषण की इस जटिल समस्या से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, उद्योगों, स्थानीय समुदायों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतों को अपनाना, औद्योगिक अपशिष्ट के लिए सख्त नियम लागू करना, और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर, समुदाय आधारित निगरानी और स्वच्छता अभियान भी प्रभावी हो सकते हैं। राजस्थान की बिगड़ती आबोहवा एक चेतावनी है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट और गहरा सकता है। यह न केवल पर्यावरणीय, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आपदा का रूप ले सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि राजस्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को बरकरार रख सके। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। सामूहिक प्रयासों से ही इस संकट से निपटा जा सकता है, और राजस्थान को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र मोहन शर्मा
वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिन्तक

"वोकल फॉर लोकल" के आव्हान को राज्य सरकार ने आत्मसात किया

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) विशेष.......

हेमेन्द्र सिंह

देश के इतिहास के पन्नों में 7 अगस्त, 1905 को स्वदेशी आंदोलन के रूप में एक नया अध्याय जुड़ा था, इस दिन कोलकाता के टाउन हाल से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का शंखनाद हुआ था। स्वदेशी को स्वाभिमान से जोड़ने वाले इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015 में इसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (नेशनल हैण्डलूम डे) के रूप में मनाने की पहल की।

स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हथकरघा को एक नई चेतना दी। वैसी ही स्वत्व एवं गर्व की छवि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के विजन में भी झलकती है और यह मंत्र अब भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का परिचायक भी बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के इस 'वोकल फॉर लोकल' के आव्हान को आत्मसात किया और अपनी ठोस नीतियों के माध्यम से इसे राजस्थान में नई बुनावट दी।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कोटा डोरिया की महीनता से लेकर सांगानेर और अज़रक प्रिंट तक की परम्परागत कला ने न केवल समृद्ध संस्कृति और सभ्यता का तराना रचा है बल्कि वस्त्र उद्योग के रुप में आज भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ताना बाना बुन रही है। कोटा डोरिया और सांगानेर प्रिंट ने देश की सीमाओं से परे अन्तर्राष्ट्रीय फैशन इंडस्ट्री में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग के नये केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025' लागू की है।

■ 'स्वदेशी' से 'आत्मनिर्भरता' तक कालजयी है हमारी विरासत राजस्थान में 'वोकल फॉर लोकल' की नई बुनावट है पंच गौरव कार्यक्रम

इसके अंतर्गत हैण्डलूम जैसे ट्रेडिशन को भी को नवीनतम तकनीक से जोड़ने के लिए पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, राज्य सरकार ने कोटा, बालोतरा, भीलवाड़ा, पाली के वस्त्र कला के उत्पादों को पंच गौरव जैसे कार्यक्रम का भी हिस्सा बनाया है।

पंच गौरव कार्यक्रम से पनपती स्थानीय पहचान :- देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते राजस्थान के सभी अंचलों में अलग-अलग पारिस्थितिकी, भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं विशिष्ट संस्कृति देखने को मिलती है। राज्य सरकार पंच गौरव कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक जिले में विशिष्ट एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल को प्रोत्साहित कर रही है।

जैसलमेर की खूबसूरत पीलू जाल (वानस्पतिक प्रजाति), प्रतापगढ़ के थेवा आभूषण (उत्पाद) की बेजोड़ कलाकृति, अनोखी महक से सराबोर बीकानेर की मेथी (उपज), सदियों पुरानी धरोहर की छवि को उकेरता नागौर का मीरा स्मारक (पर्यटन स्थल), सिरोही की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के सामर्थ्य को दर्शाती तीरंदाज़ी (खेल) इसके उदाहरण है। स्थानीयता एवं विशिष्टता के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन, पहचान एवं विकास की पंचधारा से प्रदेश के सभी अंचलों के स्थानीय तत्व अब देश-विदेश में 'ब्रांड राजस्थान' बन रहे है।

आज 7 अगस्त का दिन हमें यह याद दिलाता है कि आत्मनिर्भरता हमारे देश के लिए आत्मगौरव का विषय है। वैश्विक परिदृश्य में जब आज अन्य देश टैरिफ नीतियों की ओर बढ़ रहे है, तब हमारी कालजयी विरासत को संजोते हुए स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को विकल्प की बजाए आवश्यक रूप में अपनाने का मंत्र और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की नीतियाँ इसी दिशा में विकास और विरासत को संतुलित करते हुए एक नए एवं समृद्ध राजस्थान की बुनियाद रख रही है।

–हेमेन्द्र सिंह (सहा. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी), मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ

भारत की पेट्रोलियम कंपनियों का महाविलय: यही समय है! सही समय है!

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

आज जब भारत तेज़ी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हमें अपने संसाधनों, व्यवस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में वह क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा, जो आने वाले दशकों में देश को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाए। पेट्रोलियम सेक्टर इसकी सबसे अहम कड़ी है-और यह वही क्षेत्र है जहाँ बिखराव, विभिन्न ब्रांड, गुणवत्ता की खाइयाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में उलझन और बार-बार सामने आती घपलों-चोरियों की खबरें आम हो चुकी हैं।

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कितनी ही सार्वजनिक और निजी कंपनियाँ देश में तेल की आपूर्ति का जिम्मा उठाती हैं। लेकिन क्या ये बिखराव और प्रतिस्पर्धा जनता को वाकई बेहतर सेवा दे पा रही है? हर कंपनी का अपनी कंपाउंडिंग, अलग-अलग बफर स्टॉक्स, अलग स्टोरेज-ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, अपनी अपनी लॉबी, नेताओं-अफसरों की हिस्सेदारी, पुराना नियम-कायदा, और अंत में पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता में अंतर। क्या कभी आपने सोचा-एक शहर में दो ब्रांड के पंप पर, एक ही दिन एक ही पेट्रोल के दाम-गुणवत्ता अलग कैसे हो सकते हैं?

अब समस्या सिर्फ कीमत या उपभोक्ता के भ्रम की नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की लागत व पारदर्शिता की कमी की भी है। रोज़मर्रा के अख़बारों की हेडलाइन बनती "पेट्रोल डीजल चोरी", काला बाजारी, ट्रक-टैंकर घोटाले.. अभी ताजातरीन मामला एक अखबार की फ्रंट पेज पर, पाइप लाइन से क्रूड आयल चोरी जो कई दशकों से चल रही है और एक बड़े माफिया का रूप ले चुकी है जो अपने आप में सिस्टम की खामियों का आईना है। मर्जर से क्या-क्या बदल सकता है?

कल्पना कीजिए-यदि तीनो पेट्रोलियम कंपनियाँ मर्ज हो जाएं, उनके सभी संसाधन, पूंजी, पाइपलाइन, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, विपणन नेटवर्क एक जगह, एक छत्र-छाया के नीचे आ जाएं, तो कैसे खुलेगा तरक्की का नया रास्ता! कोई 'प्रीमियम' और कोई 'सामान्य' पेट्रोल की उलझन रहेगी ही नहीं। देश-भर में एक ही क्वालिटी, सबसे बेहतरीन ग्रेड का पेट्रोल-डीजल मिलेगा। लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज की लागत आधी से भी कम, व्यवस्था खातों किताबों के हिसाब से एकदम पारदर्शी।

बफर स्टॉक्स और इमरजेंसी स्टोरेज-जो आज हर कंपनी अलग बनाती-रखती है, वह एक सिस्टम में आ जाएगा।

जब डीलरशिप खुलेगी, तो न पारिवारिक/राजनीतिक सिफ़ारिश चलेगी, न अफसरशाही की पकड़ बचेगी-पारदर्शी नीलामी और ऑक्शन से आम आदमी को भी अवसर।

बाजार में एक ही ब्रांड, एक ही पेट्रोल-तो उपभोक्ता के मन का भ्रम भी दूर और भ्रष्टाचार को भी सीधी चोट।

जब वाहनों के लिए एक ही ग्रेड भारत का पेट्रोल-डीजल सरकार उपलब्ध कराएगी, तो प्रदूषण कम करने का लक्ष्य भी यही से साधा जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस पर नियंत्रण होगा ।

वर्टिकल मैनेजमेंट: हर डिवीजन की सीधी जवाबदेही

मेगा पेट्रोलियम कंपनी में हर उत्पाद-चाहे वह क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो या की-लुब्रिकेंट, डीजल हो या एयर टरबाइन फ्यूल- प्रॉपेन सीएनजी या पेट्रोकैमिकल्स-उसके लिए अलग-अलग वर्टिकल होंगे। हर वर्टिकल के महानिदेशक की स्पष्ट जिम्मेदारी होगी कि इंपोर्ट/खरीद, रिफाइनिंग -प्रोसेसिंग से लेकर ग्राहक को डिलीवरी तक के हर खर्च-लाभ की सटीक बहीखाते तैयार हो जायेंगे। इस तरह सालाना जब एक विशाल जम्बो बैलेंसशीट बनेगी, तो सरकार और समाज जान पाएगा कि भारत का उत्पादन, उपभोग, टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट और भविष्य की ज़रूरतें एवं वर्तमान के हालातों से रूबरू होंगे ।

अतीत से सबक, भविष्य का रास्ता

बहुत लोग कहते हैं-मर्जर में जोखिम है। मैं कहता हूं, यही वह वक्त है जब सरकार को साहसी निर्णय लेना चाहिए। जीएसटी को ही ले लीजिए, जब इसके लिए 25 से भी ज्यादा विभागों का एकीकरण हुआ, व्यापारियों से विरोध भी झेलना पड़ा, अफसरों से कड़ा सवाल भी, लेकिन जो एक देश, एक टैक्स, आज हरेक व्यापारी और उपभोक्ता सराह रहा है, वही फायदा पेट्रोलियम में भी मिलेगा।

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां-भारत को सीखना होगा

दुनिया में सऊदी अरामको जैसी कंपनियां (590 अरब राजस्व, 1.8 ट्रिलियन मार्केट कैप), सिनोपेक-चाइना पेट्रोलियम (487 अरब), पेट्रोचाइना, एक्सॉनमोबिल, शेल जैसे ब्रांड, अपनी भव्य एकीकृत व्यवस्थाओं के बल पर वैश्विक रैंकिंग में टॉप पर हैं। जब हमारी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन एक साथ होगा, तब भारत भी दुनिया की सूची में कहीं आगे बढ़ जाएगा।

दुनिया की शीर्ष तेल कंपनियों का राजस्व और मार्केट कैप:-

सऊदी अरामको (Saudi Aramco)
वार्षिक राजस्व: लगभग 590 अरब अमेरिकी डॉलर
मार्केट कैपिटलाइजेशन: 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

सिनोपेक (China Petroleum & Chemical)
वार्षिक राजस्व: लगभग 487 अरब अमेरिकी डॉलर
मार्केट कैप: 58 अरब अमेरिकी डॉलर

पेट्रोचाइना (PetroChina)
वार्षिक राजस्व: लगभग 486 अरब अमेरिकी डॉलर
मार्केट कैप: 79 अरब अमेरिकी डॉलर

एक्सॉन मोबिल (ExxonMobil)
वार्षिक राजस्व: लगभग 387 अरब अमेरिकी डॉलर
मार्केट कैप: 445 अरब अमेरिकी डॉलर

शेल पीएलसी (Shell PLC)
वार्षिक राजस्व: लगभग 365 अरब अमेरिकी डॉलर
मार्केट कैप: 202 अरब अमेरिकी डॉलर

भारत की मेगा कंपनी की संभावना

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास 13,772 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण 2,09,065 करोड़ रुपये है और इसके पास कुल रिज़र्व्स 1,72,716 करोड़ रुपये हैं। आज की तारीख में इसका शेयर भाव 148 है। कंपनी की सालाना बिक्री 7,58,106 करोड़ रुपये तक पहुँचती है और शुद्ध लाभ 13,789 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

भारत पेट्रोलियम के पास 4,273 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है, कंपनी का मार्केट कैप 1,45,665 करोड़ रुपये और रिज़र्व्स 77,112 करोड़ रुपये हैं। इसके एक शेयर का दाम अब 336 है। बीपीसीएल ने 4,40,272 करोड़ रुपये की बिक्री की और 13,337 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास 2,128 करोड़ रुपये की इक्विटी, 90,475 करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण और 49,016 करोड़ के रिज़र्व्स हैं। इस समय बाजार में इसका शेयर 425 है। बिक्री 4,34,106 करोड़ रुपये की रही जबकि शुद्ध लाभ 6,736 करोड़ रुपये रहा।

तीनों कंपनियों को जोड़ें तो कुल इक्विटी पूंजी 20,173 करोड़ रुपये, कुल मार्केट कैप 4,45,205 करोड़ रुपये और कुल रिज़र्व्स 2,98,844 करोड़ रुपये हो जाते हैं। इनकी कुल बिक्री 16,32,484 करोड़ रुपये है और मिलाजुला शुद्ध लाभ 33,862 करोड़ रुपये तक पहुँचता है।

यदि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सभी बड़ी भारतीय पेट्रोलियम कंपनियां मर्ज होकर एक "मेगा इंडिया पेट्रोलियम" कंपनी का रूप लेती हैं, तो उसके संभावित फ़ायदे और वैश्विक प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे:-

भारत की 'मेगा कंपनी' का संयुक्त वार्षिक राजस्व लगभग 200-250 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है, जिससे वह दुनिया की टॉप-5 तेल कंपनियों की कतार में आ सकती है।

बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) भी बढ़कर लगभग 200-300 अरब अमेरिकी डॉलर के लगभग पहुँच सकती है, जिससे भारत वैश्विक मंच पर दिखेगा।

जनता को पूरे देश में एक ही दर और एक ही क्वालिटी का पेट्रोल-डीजल मिलेगा, जिससे उपभोक्ता भ्रांतियां और भ्रष्टाचार दूर होगा।

आज हर राज्य की अपना टैक्स की दरें अलग-अलग होने से उनके बॉर्डर एरिया में जो पेट्रोल पम्प हैं यदि सस्ता है तो बेशुमार बिक्री होती है और अगर बॉर्डर का दूसरा पम्प महँगा है तो उसकी बिक्री नगण्य होती है और इसका उदाहरण राजस्थान - हरियाणा के बॉर्डर पर देखा जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स, बफर स्टॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज आदि पर दोहराव खत्म होगा और अनुमानतः 15-20 तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। सभी का इन्वेंटरी प्रबंधन खर्च मर्जर के बाद आधा हो जाएगा।

एकीकृत कंपनी देश के लिए निवेश, रोजगार, टेक्नोलॉजी और पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी ला सकती है।

ग्लोबल स्टेज पर भारत की ब्रांडिंग मज़बूत होगी और "वन ब्रांड, वन कंपनी, वन नेशन" का सपना साकार होगा।

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। भविष्य की जनेरशन को एक अनुकूल पर्यावरण।

नई कंपनी के बनने से सैकड़ों नई नौकरियाँ, टेक्निकल, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन में शानदार मौके।

इस तरह, भारत की एक विशाल पेट्रोलियम कंपनी विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने और उपभोक्ता जीवन आसान बनाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

देश के लिए, आम जनता के लिए

अब यह सिर्फ सरकार के सपने की बात नहीं-यह आम आदमी, टैक्सपेयर, व्यवसायी, किसान, व्यापारी, हर नागरिक के विकास का सपना है। भारत के हर कोने में एक ही दर, एक गुणवत्ता का पेट्रोल-डीजल, पारदर्शी सौदे, स्मार्ट व तेज वितरण। पाइपलाइन से गांव हो या मेट्रो सिटी, गैस-पेट्रोल के बेहतर इस्तेमाल की क्रांति।

अब बदलाव की ज़रूरत

क्या नई चुनौतियाँ नहीं होंगी? जरूर होंगी। बड़े बदलाव कभी भी बिना विरोध या टकराव के नहीं आते, लेकिन अगर लक्ष्य पारदर्शिता, दक्षता, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी और उपभोक्ता को श्रेष्ठ सेवा देना है, तो यह फैसला ऐतिहासिक होगा।

"एक कंपनी, एक ब्रांड, एक क्वालिटी, एक राष्ट्र"-अब समय है भारत को एशिया ही नहीं दुनिया की शीर्ष तेल कंपनियों के साथ बराबरी पर खड़ा देखें। सरकार, विशेषज्ञ, और समाज-सबको आगे आकर इस परिवर्तन की ओर गंभीरता से कदम बढ़ाना होगा।

यदि आपको उसका कोई हिस्सा और विस्तार से चाहिए, या और भी संचारी, भावनात्मक या तथ्यपरक भाषा में चाहिए-तो आप निर्देश दें।

धन्यवाद,

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान

राशिफल गुरूवार 7 अगस्त, 2025

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन 2:01 तक, विष्कुम्भ योग प्रातः 6:42 तक, तैतिल करण दिन 2:28 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 8:11 से मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग दिन 2:01 से आरम्भ होगा। आज आखेटक त्रयोदशी और शिव पवित्रारोपण है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ सूर्योदय से 7:37 तक, चर 10:54 से 12:32 तक, लाभ-अमृत 12:32 से 3:50 तक, शुभ 5:28 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 7:07

मेष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। मित्रों/रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

कन्या
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित संपर्क बनेंगे।

तुला
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

धनु
घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

मकर
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। आज मन में असंतोष बना रहेगा।

कुंभ
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ बनी रहेगी। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।

मीन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

सार-समाचार

27 वां वनभोज भक्तिभावपूर्वक सम्पन्न

रतनगढ़ (निसं)। लड्डू गोपाल का 27वाँ वनभोज कार्यक्रम स्थानीय अग्रसेन भवन में ललिता देवी व्यास द्वारा आयोजित लड्डू गोपाल की पिकनिक के रूप में भक्तिभाव पूर्वक मनाया गया। सावन के मौसम में वन भ्रमण कर स्विमिंग पूल में नहाने, झूला झूलने व खेलकूद कर पिकनिक का आनंद लेने के लिए नगर के कोने-कोने से लड्डूगोपाल पहुंचे। अखिल भारतीय संघ समिति जयपुर संभाग के अध्यक्ष श्री 1008 महंत विष्णुदास महाराज, अखिल भारतीय सिखवाल ब्राह्मण समिति जयपुर अध्यक्ष शशि शर्मा, पूर्व पालिकाध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, पूर्व पार्षद राहुल व्यास, सिखवाल ब्राह्मण समिति दिल्ली एन सी आर अध्यक्ष कुणाल व्यास एवं व्यास परिवार के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। समारोह के प्रारंभ में अतिथियों ने कुलदीप व्यास द्वारा लिखे गए भजनों की पुस्तक' श्री चौकवाले बालाजी, भाव-प्रवाह का लोकार्पण किया'। पिकनिक में पहुंचे 202 लड्डूगोपालों ने सबसे पहले सुसज्जित उद्यान रूपी मंच पर खेलकूद करते, झूले पर झूलते हुए विविध व्यंजनों व फलों का आनंद लिया फिर स्विमिंग सूट पहनकर विशेष रूप से बनाए गए तरण ताल के चंदन केशर युक्त जल में डुबकियां लगाई। स्विमिंग पूल में स्नान के बाद सभी गोपालों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया। गायक छोटू राजस्थानी और कुलदीप व्यास द्वारा प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालु महिलाओं ने उत्साहपूर्वक नृत्य करते हुए लड्डूगोपालों को खूब रिझाया। अभिषेक के बाद लड्डूगोपालों को नवीन वस्त्राभूषण पहनाए गए और छप्पन भोग की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष अर्चना सारस्वत, सरस्वती सिखवाल, ललिता ओझा, दमयंती सिखवाल, कविता सिखवाल, बसंती व्यास, लक्ष्मी ओझा, शकुंतला व्यास, प्रतिष्ठा सिखवाल, संगीता जोशी, अनीता ओझा, सुनीता सिखवाल, गीता राजा, मोहिता पारीक, ज्योत्स्ना ओझा सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रही।

विधिक साक्षरता क्लिनिक का शुभारंभ

झुंझुनूं, (निसं)। बुधवार को नालसा द्वारा जारी योजना वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं द्वारा जिला सैनिक कल्याण बोर्ड झुंझुनूं के कार्यालय में विधिक साक्षरता क्लिनिक का उद्घाटन जिला एवं सेशन न्यायाधीश डालसा अध्यक्ष दीपा गुर्जर द्वारा रिबन काटकर विधिवत तौर पर किया गया। दीपा गुर्जर ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) अब सैनिकों और उनके परिवारों को देश के किसी भी कोने में कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। अगर कोई जवान देश के किसी भी कोने में तैनात है और उसके गृह राज्य में किसी भी प्रकार का विधिक मामला चल रहा है तो उसके बाबत विधिक सलाह व विधिक सहायता पैरवी उक्त योजना के तहत प्राप्त जा सकेगी। झुंझुनूं जिला सैनिक बाहुल्य जिला है। जिसमें ऐसे क्लिनिक की आवश्यकता है। डालसा सचिव एडीएजे डॉ. महेंद्र के. सिंह सोलंकी ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला सैनिक कल्याण बोर्ड झुंझुनूं के सहयोग से विधिक साक्षरता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। उक्त क्लिनिक पर रिटायर्ड फौजी को पीएलवी तथा पैनल अधिवक्ता का प्रशिक्षण दिया जाकर नियुक्त किया जाएगा ताकि समयबद्ध फौजी जवानों को निःशुल्क विधिक सहायता-सलाह मिल सकेगी। ताकि वे अपनी ड्यूटी चिंतामुक्त होकर कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अनिल पूनियां एवं उनके कार्यालय के कर्मचारी व रिटायर्ड फौजी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टाफ आदि उपस्थित हुए।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

पिलानी, (निसं)। बिरला शिक्षण संस्थान की तरफ से मेजर जनरल रिटायर्ड एसएस नायर निदेशक बिरला शिक्षण संस्थान के मुख्य आतिथ्य में बिरला बालिका विद्यापीठ के बाहरी परिसीमन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पेड लगा कर समाज मे एक नया संदेश दिया। ताकि सभी लोग समाज में अधिक से अधिक पौधारोपण कर समाजहित के कार्य करें। मेजर जनरल रिटायर्ड एसएस नायर ने बताया कि हर वर्ष बिरला शिक्षण संस्थान की द्वारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाने का लक्ष्य होता है। उन्होंने बताया कि धरती पर पेड़ों और पौधों के अस्तित्व के बिना मनुष्य और जानवरों की अन्य प्रजातियों का अस्तित्व संभव नहीं है। यही कारण है कि पेड़ों को काटने की निंदा की जाती है और सरकार ने अधिक से अधिक पेडों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने बताया कि हर के व्यक्ति को अपने जीवन में पौधारोपण कर मानवजाति का संरक्षण करना चाहिए। पेड़ लगाने से आसपास के वातावरण शुद्ध होना, ऑक्सिजन का मिलना, हानिकारक गैसों से बचाव और जल प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। इसलिए पौधारोपण कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर जीएस गिल, कपिल शर्मा, डॉ. मनोज जांगिड, चंद्रशेखर राठौड, अनिल जोशी, सीमा सिन्हा, विक्रमजीत सिंह, सुरेशचंद सैनी, शिवराज सिंह रावत आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया

रतनगढ़ (निसं)। स्थानीय संगम चौराहा मेगा हाईवे पर रतनगढ़ ट्रक यूनियन के द्वारा युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राईका, रतनगढ़ ट्रक यूनियन अध्यक्ष भेरू सिंह भोजासर, रामकरण खयालिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला दहन कर वाहन चालकों की रद्द की गई आरसी को बहाल करने व ई रवन्ना चालान को रद्द किए जाने की मांग करते हुवे विरोध जिताया। राईका ने बताया कि ट्रक यूनियन की हडताल को 7 दिन हो गए हैं प्रशासन ने अभी तक ट्रक यूनियन की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की। ट्रक यूनियन की मांगे जायज है जिन पर राजस्थान सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। ट्रक यूनियन की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे राजस्थान में ट्रक यूनियन द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। इस अवसर पर सतपाल श्योराण, संदीप सिंह भोजासर, मदन सिंह भोजासर, बृजलाल खयालिया, जीतू सिंह, प्रताप सिंह, नेमीचंद प्रजापत, देवकीनंदन माहिच सहित ट्रक यूनियन के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन

उदयपुरवाटी (निसं)। कस्बे में एसबीआई बैंक के सामने सांवरिया सेठ धाम मंदिर परिसर में 13 अगस्त जन्माष्टमी के पावन पर्व पर संगीतमय श्रीमद् भागवत श्याम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कथा 20 अगस्त तक चलेगी श्रीमद् भागवत श्याम कथा का प्रतिदिन दोपहर 1.15 बजे से सायं 6:00 बजे तक का समय होगा सांवरिया सेठ मंदिर के महंत श्यामशरण मनीष महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि आठ दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत श्याम कथा की तैयारियां की जा रही है मंदिर के महंत ने बताया कि 13 अगस्त को उदयपुरवाटी खेल मैदान से सैकडों महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी भागवत कथा की पूर्ण आहुति बीस अगस्त को होगी और भंडारे का आयोजन होगा जिसमें श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी का सम्मान

रतनगढ़ (निसं)। रतनगढ़ में नव पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी मिथिलेश कुमार का लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष प्रदीप कुमार धर्ड के नेतृत्व में स्वागत किया। इस अवसर पर क्लब सदस्यों ने माला और साफा पहनाकर एसडीएम का स्वागत सम्मान किया और रतनगढ़ में उनके सफल कार्यकाल के लिए मंगल कामना की। कोषाध्यक्ष मनोज जोशी ने लॉयंस क्लब द्वारा किये जाने वाले सामाजिक सेवा के कार्यों के बारे में अवगत कराया। पूर्व सचिव संजय कटारिया ने बताया कि लॉयंस क्लब प्रशासन के सहयोग से नगर की सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। इस अवसर पर पवन कुमार तोषावड, मोहम्मद अनवर कुरैशी, सांवरमल तोषावड, ओमप्रकाश गोदारा, भींवराज भोभरिया, महेंद्र इंदौरिया, सांवरमल भूण, सुभाष सोनी उपस्थित थे।

झूलन महोत्सव आज से

उदयपुरवाटी (निसं)। धार्मिक तीर्थ स्थल लोहार्गल धाम में 7 अगस्त से 10 अगस्त तक भगवान गोधा रंगनाथ को झूला झूलाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा सिद्ध पीठ वेंकटेश बालाजी देवस्थान लोहार्गल धाम के स्वामी अश्विनी आचार्य महाराज ने बताया कि तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में गोधा रंगनाथ भगवान को झूला झूलने का कार्यकम के दौरान भगवान वेंकटेश का अलौकिक फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। झूलन महोत्सव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है

अश्वमित्र सम्मेलन आयोजित

रतनगढ़ (निसं)। रतनगढ़ में ब्रुक इंडिया संगठन द्वारा अश्वमित्र सम्मेलन अयोजित किया गया जिसमें 60 अश्वपालकों ने भाग लिया। सम्मलेन में ब्रूले इंडिया द्वारा अश्वपालकों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया और अश्वपालकों ने अपने विभिन्न कार्यों के बारे में सांझा किया। सम्मेलन के दौरन जेडपीसी अंजल, एसपीसी महेश और डॉ. अनिता और ब्रुक का स्टाफ उपस्थित रहे।

एनएसयूआई ने छात्र चेतना यात्रा निकाली

- छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग

चूरू (निसं)। प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र इकाई एनएसयूआई अब सड़कों पर उतर आई है।

छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर जेएनयू जोधपुर से शुरू हुई छात्र चेतना यात्रा बुधवार को चूरू पहुंची। यहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुरानी कलेक्ट्रेट पहुंचने पर यात्रा का भव्य स्वागत किया और लोहिया कॉलेज तक छात्र चेतना यात्रा निकालकर आक्रोश व्यक्त किया।

यात्रा में प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी। इस अवसर पर एनएसयूआई के राजस्थान विष्व विद्यालय के छात्र नेता अभिषेक चौधरी ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है और यह चुनाव होंगे तभी छात्रों की आवाज सदन तक पहुंचेगी।

महेंद्र चौधरी ने कहा कि जब तक छात्र अपने हक के लिए नहीं जागेगा, तब तक किसी का भला नहीं हो सकता। इस अवसर पर एनएसयूआई के पूर्व महासचिव पुलकित चौधरी ने कहा कि सरकार छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाकर युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। सोयल खान डीके ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार युवा विरोधी है। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो महाविद्यालयों में व्याप्त अव्यवस्थाओं के मुद्दों को कौन उठाएगा।

यात्रा के लोहिया कॉलेज पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल ने प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया। इस अवसर पर निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष अनिल भाकर, छात्र प्रतिनिधि अमन चौधरी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनिता कपूरिया, छात्र नेता सूफियान झारिया, छात्र नेता राहुल कुमार, मोहित खान, अनिल भाकर, राकेश कस्वां, राकेश सिरसली, रोहन वैष्णव, अनिल कस्वां, अमित मेहरा, नरेंद्र मेहरा, लतिफ खान, आदिल गौरी, सोयल खान, अजीत आचार्य, रहीम खान, कार्तिक स्वामी, चिराग, करणीदान चारणवासी, अजीत सिंह, अजय चौधरी, गोविंद शर्मा, देवेंद्र खीचड़, मोनू पंडित, कपिल, शिव, पवन फोगावट, कुलदीप, अक्षय, अमन पूनिया, मोनू राजगढ़, राहुल सैनी, भारती, कोमल, केसर, मुस्कान आदि उपस्थित थे।

कासिमपुरा स्कूल में बैग बांटे

झुंझुनूं, (निसं)। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उदयपुरवाटी की ओर से प्रबंधक संग्राम सिंह शेखावत ने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत स्वतंत्रता सैनानी श्री रिछपाल राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमपुरा में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए। इस अवसर पर विद्यालय की प्रेरक माया राठौड एवं संस्था प्रधान मुकेश कुमार ने बैंक की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति उत्साह और लगन में वृद्धि होगी।

स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति की बैठक आज

गुढ़ागौड़जी, (निसं)। कस्बे में स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति के जेपी महला ने बताया कि स्मार्ट मीटर के विरोध में चल रहे आंदोलन को तेज करने को लेकर गुरुवार सुबह 10 बजे अभिनंदन मैरिज गार्डन में सरकारी अस्पताल के पीछे गुढागौडजी में जागरूक प्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है। मीटिंग 20 अगस्त को जिले भर में होने वाले बंद को लेकर सभी व्यापार मंडलों से चर्चा करने, स्मार्ट मीटर हटाने का सरकार आदेश वापस ले। लगाए गए सभी स्मार्ट मीटर हटाए जाए तथा घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर सभी बिजली पॉवर हाउसों पर कमेटी का गठन किया जाएगा।

पुलिस अधिकारियों को रक्षासूत्र बांधे

सादुलपुर, (निसं)। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सादुलपुर की ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व के मनाया जा रहे सप्ताह के अंतर्गत पुलिस थाना राजगढ जिला चूरू में रक्षासूत्र बांधने का कार्यक्रम राजेश कुमार सिहाग सीआई पुलिस थाना राजगढ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बुधवार शाम चार बजे दी जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी शोभा बहन थी।

उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा की रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश के लिए सबसे बडा त्यौहार हैं। जिसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इस त्यौहार में सभी सदगुण छिपे हुए हैं। इसको अगर भारत के लोग समझ जाए और इसके अंदर छिपे हुए राज को जीवन में धारण कर ले तो यह त्यौहार सतयुग दुनिया का प्रवेश द्वार बनेगा। यह सिर्फ बहन भाई का इतिहास नहीं है बल्कि समस्त मानव जाति के सुख चैन की दुनिया का आईना भी है।

इस अवसर पर राजेश कुमार सिहाग सी आई राजगढ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा की नारी जाति का सम्मान करना हमारी संस्कृति तथा उनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसी दौरान पुलिस बल के समस्त उपस्थित जनों की कलाई पर बीके शोभा बहन ने रक्षा सूत्र बांधा एवं उनके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना की।

वहीं पूनम बहन ने सभी के माथे पर विजय का तिलक लगाया और उन्हें परमात्मा की ओर से दिव्य वरदान दिया। तथा आश्रम का प्रसाद देकर मुख मीठा भी करवाते हुए सभी से आज के दिन कोई एक कमजोरी छोडने का संकल्प भी दिलाया। इस अवसर पर एडवोकेट बृजमोहन शर्मा एवं शिक्षाविद प्रताप सिंह भोजनीया ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

इस अवसर पर राजेश कुमार सिहाग सीआई, रामनिवास एएसआई, राकेश हैड कास्टेबल, सुनील हैड कांस्टेबल, राजकुमार हैड कास्टेबल, कुलदीप रीडर, जलेसिंह कास्टेबल, सुबेसिंह कास्टेबल, पवन कांस्टेबल, विजेन्द्र कास्टेबल, संदीप कांस्टेबल मुकेश कास्टेबल एजीटीएफ, मनोज कांस्टेबल, सुशीला महिला कांस्टेबल एवं समस्त स्टाफ के सदस्यों ने सहयोग किया।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित

- प्रतियोगिताओं में विजेता स्वयं सहायता समूह राजीविका की महिलाओं को किया पुरस्कृत
- जिला स्तरीय हाट मेले का समापन

सादुलपुर, (निसं)। हाट मेले के समापन पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगरपालिका राजगढ द्वारा बुधवार ०6 अगस्त 2०25 को राजकीय स्कूल के खेल मैदान में रंगोली, मेहँदी एवं तिरंगा राखी प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया गया। शाम पांच बजे दी जानकारी के अनुसार इस आयोजन में स्वयं सहायता समूह (राजीविका) की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मकता व देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता का परिचय दिया।

रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ममता, द्वितीय स्थान सरोजबाला एवं तृतीय स्थान सुमन ने प्राप्त किया। मेहेंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सरिता, द्वितीय प्रिया एवं तृतीय स्थान निर्मला ने हासिल किया। तिरंगा राखी प्रतियोगिता में प्रथम कविता लम्बोर बडी, द्वितीय कविता हमीरवास एवं तृतीय स्थान पर सुमन सांखू रही। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से महिलाओं ने अपने हाथों से भारत के गौरव तिरंगे झंडे को अपनी रचनाओं में जीवंत किया। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवी संगठनों की महिलाओं द्वारा देशभक्ति गीतों पर भावविभोर कर देने वाली प्रस्तुतियाँ दी गई, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा ने महिला प्रतिभागियों की सराहना करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने व शिक्षा एवं सामाजिक नेतृत्व में आगे बढने तथा स्वच्छता के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार अरोडा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रप्रेम, स्वच्छता एवं जनजागरूकता पर विशेष बल दिया।

उन्होंने उपस्थित नागरिकों एवं महिलाओं से आव्हान किया कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं व पर्यावरण व स्वच्छता को जीवन में अपनाएं और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। मंच संचालन भाजपा युवा नेता कृष्ण भाकर ने किया। इस अवसर पर नगरपालिका के कर्मचारीगण जयंत सांगवान, दीपक, कालीचरण उपस्थित रहे। सभी ने नागरिकों से आव्हान किया कि वे अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराएं व स्वच्छता को अपनाएं और राष्ट्रहित में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित

लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी (निसं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिड़ोदी में मंगलवार को भामाशाह व प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य अंबिकेश गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागीरथ मल गोदारा पंचायत समिति सदस्य विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम योगी, संदर्भ व्यक्ति सुरेश कुमार भास्कर, राजेंद्र प्रसाद प्रतिनिध थे। कार्यक्रम के संयोजक दिनेश कुमार ने बताया कि इस अवसर पर अतिथियों द्वारा विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों के साथ- साथ विद्यालय में आर्थिक सहयोग करने वाले दानदाताओ एवं भामाशाहओ का भी साफा, प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्यख्याता प्रमोद कुमारी ने किया। सम्मान समारोह में जगदीश भास्कर पूर्व अध्यापक, ब्रजमोहन भास्कर, ईश्वर सिंह, रामकरण राजपाल, सुखदेव राम, फूलचंद, ताराचंद, नेमीचंद, प्यारेलाल भास्कर, रामस्वरूप भास्कर सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

एसएससी की परीक्षाओं में अनियमितताओं से युवाओं के साथ हो रहा बड़ा अन्याय : सांसद राहुल कस्वां

- लोकसभा में नियम-377 के तहत्त बोले सांसद कस्वां, युवाओं के साथ सुनियोजित खिलवाड़ हो रहा है जिस पर तत्काल रोक लगे

चूरू (निसं)। चूरू लोकसभा से सांसद राहुल कस्वां ने सदन में नियम-377 के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर की भर्तियों में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लगातार की जा रही अनियमितताओं का मुद्दा उठाया।

उन्होंने सदन के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए कहा कि द्वारा आयोजित हो रही परीक्षाओं में भारी अनियमितताओं से युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है। परीक्षा आयोजन में बार-बार देरी, बगैर सूचना दिए परीक्षा स्थगित करना, गलत सवाल पूछना, सैंकड़ों किमी. दूरी पर परीक्षा केन्द्र देना, उत्तर कुंजी में अनेकों त्रुटियाँ, परिणामों में पारदर्शिता की कमी जैसे विषयों को लेकर छात्र और शिक्षक आन्दोलित हैं।

देशभर से लाखों अभ्यर्थियों ने एसएससी द्वारा आयोजित हुई परीक्षाओं में भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें हर बार गंभीर अव्यवस्था, असमानता और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता। विशेष चिंता का विषय यह है कि कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर रात 10 बजे तक रोका गया, जो उनकी सुरक्षा, गरिमा और मानसिक स्थिति पर सीधा हमला है। इन सभी कारणों के चलते युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ रहा है।

सांसद कस्वां ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही शिकायतों की लगातार उपेक्षा बाद उनको अपनी तैयारी छोड़ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन के लिये मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कठोर दमनात्मक कार्यवाही की गई और उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। एक परीक्षा में गड़बड़ी का मतलब है लाखों उम्मीदों का चकनाचूर हो जाना। अनेकों समस्याओं से जूझते हुए वर्षों से तैयारी करने वाले युवाओं के सपनों को सुनियोजित ढंग से कुचलने का प्रयास अत्यंत ही गंभीर मामला है।

सांसद कस्वां ने केन्द्र सरकार से इस विषय पर त्वरित संज्ञान स्वतंत्र तकनीकी जांच करवाने, निजी परीक्षा एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा करने, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित करनी की मांग की। उन्होंने कहा कि एसएससी जैसी संस्थाओं देश के युवाओं का भरोसा उठना अत्यंत ही गंभीर है। सरकार युवाओं की मांगों के अनुरूप तत्काल कड़े कदम उठाकर व्यवस्था को पारदर्शी बनाए।

शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद भी जरूरी : मंडेलिया

राजलदेसर (निसं)। युवा भारती स्टेडियम में राजलदेसर कुरैशी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें लोशल की टीम विजेता रही उपविजेता राजलदेसर इस्लामिया रही। मैन ऑफ द मैच गुलफाम नागोरी, मैन ऑफ द मैच सीरीज अरशद खत्री रहे। विजेता टीम को ट्रॉफी व 41 हज़ार रूपयों की नगद राशि दी गयी।

वहीं उपयोगिता टीम को ट्रॉफी व 21 हजार रूपये नगद राशि भेंट की। जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुरैशी समाज के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, कुरैशी समाज के प्रदेश सचिव साजिद सुलेमान, विशिष्ट अतिथि सलीम बेहलीम, नगर कांग्रेस कमेटी के जब्बार खोखर, पार्षद नवी बक्स, इदरीश खत्री आदि मंचस्थ अतिथि रहे।

इस अवसर पर कुरैशी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मकबूल मंडेलिया ने कहा कि खेल में हार जीत कोई मायने नहीं रखता लेकिन इस तरह के समाज में कार्यक्रम होने चाहिए साथ ही शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद भी जरूरी है क्योंकि कुरैशी समाज 20 वर्ष पिछडा हुआ है। अब हर जगह पर समाज स्तर पर शिक्षा खेलकूद सामाजिक एकता आदि को लेकर पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा।

इस अवसर पर प्रदेश सचिव ने कहा कि राजलदेसर कस्बे के अंदर एक छोटे से गांव में इतना शानदार स्टेडियम देखकर बहुत खुशी हुई है। यहां के भामाशाहों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।

जिन्होंने सर्व समाज के लिए इतना शानदार स्टेडियम का निर्माण कराया साथ ही उन्होंने कहा विजेता, उपविजेता टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने बहुत ही अनुशासन तरीके से खेल को खेल की भावना से खेला एवं आयोजन कर्ताओं को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया।

अतिशीघ्र ही कुरैशी समाज पूरे प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। जिसमें राजलदेसर में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस असलम बगड, अमजद निर्बाण, शरीफ बेहलीम, रिजवान बगड सहित अनेकों खेल प्रेमी मौजूद रहे।

पौधारोपण कार्यक्रम

झुंझुनूं, (निसं)। अलसीसर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में हरियाली राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

निविदा सूचना
निविदा क्रमांक BBC/PM/05 और BBC/PM/06 बाधनी बंधेज(टाई एंड डाई) क्लस्टर चूरू के अंतर्गत प्लांट मशीनरी के टर्नकी प्रोजेक्ट हेतु इच्छुक सप्लायर से निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 26.08.2025 सांय 5 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है, विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करे;
Https://ppdcagra.dcmsme.gov.in/Tender.html
Ashyana Sansthan Project Director

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-33/1151-1158 Date 04.08.2025
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय:- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 53, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।
1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 53, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।
अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखत सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-34/1159-1166 Date 04.08.2025
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय:- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 55, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।
1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 55, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।
अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 2:15 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखत सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-31/1135-1142 Date 04.08.2025
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय:- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 56, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।
1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 56, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।
अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 1:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखत सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-32/1143-1150 Date 04.08.2025
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय:- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 57, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।
1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 57, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।
अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 12:15 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखत सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-029/119-1126 Date 04.08.2025
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय:- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 54, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।
1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 54, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।
अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को प्रातः 10:30 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखत सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-30/1127-1134 Date 04.08.2025
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय:- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 58, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।
1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 58, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।
अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 3:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखत सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

देवली में एसडीएम ने अपने आवासीय परिसर में लगे हरे-भरे वृक्ष कटवाये

मौके पर मजदूर ने बताया कि उपखंड अधिकारी के आदेश पर हरे वृक्षों की कटाई की जा रही है

देवली, (निसं)। जहां हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश सहित जिलेभर में वृक्ष प्रेमियों द्वारा और सरकार की ओर से आए दिन पौधारोपण किया जा रहा है, वहीं देवली उपखंड अधिकारी और अधिशासी अधिकारी ने प्रतिबंधित हरे-भरे वृक्षों की बलि ले ली। एक और तो राज्य की भजनलाल सरकार पौधारोपण के साथ-साथ पौधों को वृक्ष बनाने तक के लक्ष्य का संकल्प दिलवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भजनलाल सरकार के ही अधिकारी फल-फूल रहे हरे-भरे वृक्षों को कटवाने की हटधर्मिता अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

देवली उपखंड अधिकारी आवासीय परिसर में लगे नीम, सफेदा के वृक्ष काट दिये।

- **पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा प्रतिबंधित हरे-भरे वृक्षों की कटाई के मामले पर गुमराह करते रहे**

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पौधारोपण करवाने जाने के लिए सरकारी एजेंसियों को लाखों के बजट के साथ पौधारोपण कार्यक्रम करवाकर सफल बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वहीं इस कार्यक्रम में शामिल आमजन सहित वृक्ष प्रेमियों को इससे प्रेरणा मिलती है। वहीं यह भी बताया जाता है कि वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध दुरुस्त बनाए रखने में कितने महत्वपूर्ण और कितने जरूरी है। परंतु यहां नीम, सफेदा और अन्य वृक्षों और पौधों को कटवाया जा रहा है।

देवली उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने अपने आवासीय परिसर में लगे हरे घने वृक्ष नीम, सफेदा इत्यादि किस्म के वृक्षों और पौधों को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के सहयोग से पूरी तरह कटवा दिए। यह मामला प्रकाश में आने के बाद जब उपखंड अधिकारी रूबी अनुसार को मीडिया द्वारा यह जानने के लिए फोन किया गया कि उपखंड अधिकारी आवास परिसर बगीचे के हरे-भरे वृक्षों को किस कारण से कटवाया जा रहा है तो इस पर उपखंड अधिकारी ने मीडिया का फोन बार-बार काट कर अड़िग रहते हुए अपनी हटधर्मिता दर्शा दी और परिसर के बगीचे के वृक्ष कटते चले गए। इस दौरान हरे वृक्षों को काटने वाले मजदूर से जानकारी चाही कि यह हरे वृक्ष क्यों और किसके आदेश पर काटे जा रहे हैं, तो मजदूर महावीर प्रसाद माली ने जानकारी दी कि उपखंड अधिकारी के आदेश पर हरे वृक्षों की कटाई की जा रही है। इसके लिए देवली नगर पालिका ने मजदूरी पर उसे यह कार्य करने के लिए कहा है। मामला यह भी सामने आया कि जिन हरे वृक्षों की कटाई की गई उनके भारी भरकम तनों (लकड़ियों) को मशीनों से काटा गया है। इतना ही नहीं इस मामले में पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा प्रतिबंधित हरे-भरे वृक्षों की कटाई के मामले पर विशालकाय वृक्षों को काटने की वजह बताने पर अलग-अलग बात कह कर गुमराह करते रहे।

उल्लेखनीय है कि गत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया था। एक और तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मां के नाम एक पेड़ लगाने की योजना पर प्रदेशभर में करोड़ों की तादाद में पौधारोपण करवाते हुए प्रधानमंत्री की इस योजना को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों भी इस कार्यक्रम के तहत पौधा लगाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन उपखंड अधिकारी आवास परिसर के बगीचे में काटे गए वृक्षों के मामले में किसी भी नेता या उच्च अधिकारी ने वृक्षों की कटाई को रोकने तक का प्रयास नहीं किया, और हरे भरे प्रतिबंध वृक्ष उपखंड अधिकारी की हटधर्मिता पर कटते चले गए।

सुरेश कुमार मीणा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका देवली टोंक का कहना है कि उपखंड अधिकारी परिसर के बगीचे में लगे हरे वृक्षों की छंगाई के लिए नगर पालिका की ओर से मजदूर लगाए गए हैं। मजदूरों ने हर वृक्षों को पूरी तरह काट दिया, इस मामले का पता करवाता हूं।

जर्जर स्कूल भवन की छत ढही

उदयपुर, (निसं)। जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके कोटड़ा के महाड़ी बंबूरिया फला साकरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत बुधवार को अचानक ढह गई। हादसा सुबह छह बजे हुआ उस समय स्कूल में शिक्षक और छात्र कोई भी नही थे इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर उपखण्ड अधिकारी हंसमुख कुमार मौके पर पहुंचे और जेसीबी कीमदद से मलबा हटवाकर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पास स्थित दूसरे भवन में स्कूल का संचालन शुरू करवाया। शिक्षकों के अनुसार गत दो वर्षों से भवन की हालत खस्ता है, जिसकी सूचना उच्चस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे चुके हैं। शिक्षक अरविन्द के अनुसार स्कूल भवन की जर्जर हालत के कारण नामांकन 225 से घटकर 190 हो गया है। यह स्कूल 2021-22 में क्रमोन्नत हुआ तब से अतिरिक्त कमरे की भी मांग कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं होने से जर्जर भवन में बने दो कक्ष में ही स्कूल चलाना पड़ रहा है।

कुराबड ब्लॉक में लैपर्ड का आतंक

उदयपुर, (निसं)। जिले के कुराबड़ ब्लॉक में आतंक का पर्याय बने लेपर्ड ने मंगलवार रात में दो अलग-अलग गांवों में तीन श्वानों को अपना शिकार कर ग्रामीणों को और भयभीत कर दिया है। पहली घटना ग्राम पंचायत गुडली के काली मगरी गांव की है। जहां ग्रामीण भेरूनाथ के घर के बाहर बैठे पालतू श्वान को लेपर्ड ने अपना शिकार बना लिया। दूसरी घटना बोरी ग्राम पंचायत के आछट गांव की है जहां लेपर्ड ने दो श्वानों को अपना निवाला बना लिया। श्वानों के चिल्लाने की आवासज सुन कर ग्रामीणों ने जाकर देखा तो लेपर्ड तेजी से भागता दिखा।

कार्यालय नगर पालिका, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

क्रमांक : न.पा.ई./2025-26/1778 दिनांक : 04.08.2025

NOTICE INVITING BIDS

Bid for Nagar Palika Indragarh of Procurement are Invited from Interested Bidders Up to 11.00 AM , 04.08.2025 To 20.08.2025. Other particulars of the Bid Amy be Visited on the Procurement Portal (http://sppp.raj.nic.in) or (www.gem.gov.in) of the State, and local self Departmental Website.

NIB Code :- DLB2526A4350
UBN :- 1. DLB2526SLRC13716
2. DLB2526SLRC13717

अध्यक्ष नगर पालिका इन्द्रगढ़ — अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका इन्द्रगढ़

राज.संवाद/सी/25/7666

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DN GHATOL DISTT BANSWARA (RAJ)

No. 312 Date: 25.07.2025

Notice Inviting Bid No. 02/2025-26

NIB- PWD2526A2221

Bids for Rate Contract of Road Repair and Maintenance Works are invited from interested bidder's upto 19.08.2025, 06.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal ("http://www.eproc.rajasthan.gov.in nd http://www.sppp.rajasthan.gov.in) of the state. The approximate value of procurement is rs. 215.00 Lacs

UBN- PWD2526WSOB08033, TO PWD2526WSOB08038

(Naresh Shersya)
Executive Engineer
PWD Division Ghatol
Distt. Banswara

DIPR/C/10830/2025

MBM UNIVERSITY, JODHPUR

Advertisement No. :- MBMU/DFOEA/ADVT/2025/15 Dated :- 31/07/2025

Admission Notice - 2025-2026

Ph. D, P.G., B. Plan and ADCGC Course

Applications are invited from eligible candidates for admission Ph. D, P.G., B. Plan and Advance Diploma in Child Guidance and Counselling Course in MBM University, Jodhpur. Interested candidates should apply online on the MBM University website on or before 11 August, 2025, and deposit the application fee online. It is essential to submit the hard copy of their application forms along with proof of application fee and all requisite documents on or before 05:00 PM, 18 August 2025 in the respective Department of the MBM University, Jodhpur (Raj.). All further information will be given only on the University website **https://mbm.ac.in, admission.mbmiums.in.**

Raj.Samwad/C/25/7616 Registrar, MBM University, Jodhpur

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RAJASTHAN STATE HIGHWAYS AUTHORITY, JAIPUR

No.Raj Kaj No. 16935834 Date: 04.08.2025

NIT NO. 23/2025-26
NOTICE INVITING BID

Bids for "Routing maintenance of Ajeetgarh-Chala section of SH-13, Sikar-Ganeri Jaswantgarh section of SH-20 & 20A, Bidasar-Nokha section of SH-20 and Singhana-Buhana-Haryana border Section of SH-13B (total length: 233.955 Km)" are invited from interested bidders upto 11.30 AM on 11.08.2025. The date of opening of bids if 11.08.2025 at 12.00 PM.
Other particulars of bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in) of the state. The estimated value of aforementioned work is Rs. 192.60 Lakh.

UBN NO. PWD2526WSOB08825

(Akshay Kumar Jain)
Member (C & PPP),
RSHA, Jaipur

DIPR/C/11067/2025

25 लाख की अवैध शराब पकड़ी, दो गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निसं)। डूंगरपुर जिले की बिछीवाडा थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन गुजरात शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए की शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक के साथ दो तस्कर भी गिरफ्तार किए हैं।

- **ट्रक के भीतर बनाये गये गुप्त चैंबर में शराब भरी मिली**

बिछीवाडा पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि शराब से भरा ट्रक उदयपुर की तरफ से गुजरात जा रहा है। सूचना पर बिछीवाडा थानाधिकारी कैलाश सोनी के नेतृत्व में रतनपुर गुजरात सीमा पर नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान चौकी प्रभारी गोविंदसिंह ने हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में बायो मास ब्रिक भरा हुआ था। वहीं ट्रक के भीतर गुप्त चैंबर बनाकर शराब भरी हुई पाई गई। ट्रक चालक से शराब संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वो कोई जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने हिसार हरियाणा निवासी ट्रक ड्राइवर वीरसिंह और उसके सहयोगी वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ट्रक से शराब को उतरवाकर गिनती की तो ट्रक में 25 लाख रुपए की 386 पेटी अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी, जो हरियाणा निर्मित थी। पुलिस ने ट्रक सहित अवैध शराब को जप्त कर लिया है। वहीं आबकारी अधिनियम में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विद्युत केबल चोरी का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

पावटा, (निसं)। बोरवेल की विद्युत कबिल चोरी में शामिल दो आरोपियों को विराटनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी की घटना का पर्दाफाश किया है।

- **अज्ञात चोर बोरवेल की करीब 1900 फीट विद्युत केबल काटकर ले गए थे**

पुलिस अधीक्षक जिला कोटपुतली बहरोड़ देवेंद्र विश्नोई ने बताया कि वर्तमान में पुलिस मुख्यालय द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली वैभव शर्मा के निर्देशन व वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन एवं विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मुल्जिमों की गहनता से तलाश करते हुए घटना स्थल के आसपास व संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। वहीं पुलिस की तकनीकी प्रणाली की सहायता से बदमाशान की तलाश की जाकर चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए प्रकाश उर्फ कालूराम पुत्र जयराम निवासी ढाणी कोल्डावाली तन बिशनगढ़ थाना मनोहरपुर, राजू उर्फ भूरिया पुत्र बल्लू उर्फ फकीरिया निवासी तिराहा माजिका बाग अचरोल थाना चंदवाजी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी है। विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल ने बताया कि एक अगस्त को परिवादी लालाराम सैनी पुत्र रामसहाय सैनी ढाणी चैनाकी तन मैड ने मामला दर्ज करवाया था कि अज्ञात चोर बोरवेल की करीब 1900 फीट विद्युत केबिल को काटकर चोरी कर ले गए। जिस पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर

111, सहेली मार्ग, उदयपुर (राज.) पिन 313001 दूरभाष 0294-2415171, E-mail:- director.rscert@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- राराशैअप्रप-उदय/स्टोर/2025-26/1173 दिनांक :- 05/08/2025

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि RSCERT, उदयपुर द्वारा अनुपयोगी/अप्रचलित/नकारा सामग्री जिनकी Book Value IT Equipments/Electronics Rs. 3017786 एवं Non IT Equipments - Furniture etc. Rs. 175964 है की सार्वजनिक नीलामी जहाँ है जैसी स्थिति में है उस आधार पर दिनांक 29.08.2025 को प्रातः 11.30 बजे से कार्यालय के परिसर में की जावेगी। नीलामी योग्य सामग्री का अवलोकन एवं नीलामी की अन्य शर्तें कार्यालय समय में कार्यालय में देखी जा सकती है।

निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

राज.संवाद/सी/25/7662

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

Tel No. 1462-258665, 257509 Email Add: npbeawar@gmail.com

क्रमांक/निर्माण/2025-26/5958 दिनांकः- 04.08.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 08/2025-26

नगर परिषद, ब्यावर द्वारा परिषद क्षेत्र में SFC, FFC एवं परिषद कोष के अन्तर्गत निम्नांकित निर्माण कार्य करवाया जाने हेतु परिषद के सम्बन्धित श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों से E-Procurement प्रकिया के तहत केवल www.eproc.rajasthan.gov.in की ऑनलाईन निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 20/08/2025 सांय 06:00 बजे तक निविदा भरी जा सकती है एवं ई-निविदा फार्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि नगर परिषद के Axis Bank के खाता संख्या 914010005810609 आई.एफ.सी. कोड UTIB0001825 में जमा कराकर बोली धरोहर का डी.डी./बैंकर चैक नगर परिषद, ब्यावर के निर्माण शाखा में दिनांक 21/08/2025 को प्रातः 11 बजे से पूर्व जमा कराना अनिवार्य कराना अनिवार्य है। कुल 04 निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 31.67 लाख रूपये है। ई-निविदा सूचना की समस्त शर्तें SPPP पोर्टल पर देखी जा सकती है।

जिसका NIB Code DLB2526A4329 है एवं UBN नम्बर निम्नानुसार हैः-
(i) DLB2526WSOB13676 (ii) DLB2526WSOB13678 (iii) DLB2526WSOB13680 (iv) DLB2526WSOB13681

आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर — प्रशासक नगर परिषद, ब्यावर

राज.संवाद/सी/25/7652

39 टीचर्स के डेपुटेशन रद्द किये

बीकानेर, (निसं)। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के कुल 39 टीचर्स के डेपुटेशन रद्द कर दिए हैं। ये टीचर्स वेतन तो शिक्षा विभाग से ले रहे थे, लेकिन काम दूसरे विभाग में कर रहे थे। 39 में से 37 टीचर्स तो अलग-अलग जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऑफिस में ही वर्ष से जमे हुए थे। वहीं भरतपुर और कोटा कलेक्टर ऑफिस में डेरा डाले दो अध्यापकों को भी वापस विभाग में तलब कर लिया गया है।

- **39 में से 37 टीचर्स तो अलग-अलग जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऑफिस में लगे हुये थे**

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने राज्य सरकार के एक आदेश की पालना में डेपुटेशन रद्द किए हैं। राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का ऑफिस है। इसी ऑफिस में कहीं सीनियर टीचर तो कहीं ग्रेड सैकेंड के टीचर डेपुटेशन पर चल रहे हैं। अब अल्पसंख्यक मामला विभाग मदरसा बोर्ड जयपुर और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में बैठे सभी टीचर्स को हटा दिया गया है। कुछ शारीरिक शिक्षक (पीटीआइ) भी खेल मैदान के बजाय इन ऑफिस में काम कर रहे थे। अब इन सभी को यहां से हटाया गया है। कोटा और भरतपुर के जिला कार्यालय में कार्यरत दो टीचर्स की प्रतिनियुक्ति भी निरस्त कर दी गई है। इन सभी को कार्यमुक्त करने के बाद संबंधित जिले के संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए कार्यमुक्त करना होगा।

छह गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। अवैध गांजा तस्करी के मामले में फरार छह आरोपियों को घंटाघर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर घंटाघर थानाधिकारी सुनिल शर्मा के नेतृत्व में गठित दल ने गांजा खरीद फरोख्त मामले में फरार आरोपी कमल उर्फ गोलु, विजय उर्फ दादु पुत्र खेमराज, लक्ष्यराज सिंह उर्फ भरत पुत्र विजय सिंह, भावेश पुत्र ललित, सुनील उर्फ टेणी पुत्र गणेश निवासी एकलव्य कॉलोनी अम्बामाता, रामनाथ पुत्र चंदुनाथ निवासी जेकडा वाघपुरा हाल धानमण्डी को गिरफ्तार किया है।

खेतों पर लगी विद्युत केबल चोरी

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के मांडल थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं से आमजन में भय दिखाई दे रहा है। वहीं पीड़ित परिवारों में रोष है। मंगलवार रात को चोर क्षेत्र के भीमड़ियास गांव में आधा दर्जन से अधिक खेतों पर लगे विद्युत केबल को काटकर फरार हो गए। सुबह जब किसान खेत पर पहुंचे तो किसानों के खेतों पर लगी ट्यूबवेल की केबल और कुओं पर लगी विद्युत केबल कटी हुई मिली। इस पर अन्य ग्रामीणों को घटना के बारे में अवगत कराया। सभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले भी कई बार चोरी की वारदातें हो चुकी है। लगातार चोरी की घटनाओं के कारण लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। पीड़ितो में गांव के ही गोपाल बलाई, पन्नालाल बलाई, शंकरलाल बलाई, सोहन बलाई, कैलाश कामड़, भैरू लोहार सहित कई किसानों के यहां पर खेतों में चोरी की घटनाएं हुई है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद

(राजीविका) जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, चौपाल भवन, बड़ोदिया बस्ती, रेल्वे जंक्शन के पास, जयपुर (राज.)
E-mail- dpm.jaipur@yahoo.com, Ph.No. 0141-2209370

क्रमांक :- प. 4(1)डीपीएमयू/संस्थापन/2025/287 दिनांक :- 28/05/2025

संशोधित बिड सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी बिड़ सूचना संख्या-240 दिनांक 18.07.2025 UBN No.-RGA2526SLRC00114 में बिड़ प्रपत्र की Technical Bid Data Sheet के बिन्दु संख्या-6 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1. A Self Declaration for not being black listed by any Procuring entity if Debarred by the State Government and Rajasthan Gramin Ajivika vikas Parishad Department During the last 3 years with seal & Sign of Authorised Signatory.

उक्त के अतिरिक्त बिड़ प्रस्तुत करने, कार्यालय में डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने एवं बिड़ खोलने की दिनांक भी निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

क्र. सं.	Activity	संशोधित दिनांक	समय
1	Last Date & Time for Submission for Bid	13.08.2025	11:30 AM
2	Last Date & Time for Submit Physical Demand Draft (DD)	13.08.2025	12:00 PM
3	Date & Time of Technical Bid Opening	13.08.2025	12:30 PM

राज.संवाद/सी/25/7643 जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, जयपुर

डीडवाना-कुचामन में सड़क हादसे रोकने के लिये "सेफ आई-सेफ हाइवे" अभियान शुरू

सड़क हादसों को रोकने की दिशा में एक अनोखा और सराहनीय कदम उठाया, हादसों पर लगाम लगेगी

डीडवाना, (निसं)। कुचामन जिले में सड़क हादसों को रोकने की दिशा में एक अनोखा और सराहनीय कदम उठाया गया है। जिले में पहली बार "सेफ आई-सेफ हाइवे" अभियान की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ छापरी-दौलतपुरा टोल प्लाजा से राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने किया। इस मौके पर मंत्री चौधरी ने अभियान को सड़क हादसों में कमी लाने वाला प्रयास बताया और कहा कि यह केवल स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि जनजीवन को बचाने का मिशन है, जिसे वे पूरे प्रदेश में लागू करवाने के लिए सरकार से चर्चा करेंगे।

अभियान के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों की जांच कर नि:शुल्क चश्मे दिए।

- **यह अभियान केवल स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि जनजीवन को बचाने का मिशन है, जिसे पूरे प्रदेश में लागू करवाने के लिए सरकार से चर्चा करेंगे : राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी**
- **अभियान का शुभारंभ छापरी-दौलतपुरा टोल प्लाजा से राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने किया**

इस अभियान के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के चालकों, खासकर ट्रकों के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चालकों की आंखों की रोशनी, बीपी, शुगर और बीएमआई की जांच की गई और जिनकी नजर कमजोर पाई गई, उन्हें मौके पर ही नि:शुल्क चश्मे दिए गए। ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या सामने आने पर उन्हें फौरन दवाइयां और परामर्श भी दिया गया।

जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि अभियान के पहले ही दिन 300 से ज्यादा चालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिनमें से कई को चश्मे और दवाइयां दी गईं। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न टोल प्लाजा पर अब हर महीने तीन शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें चिकित्सा, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त भागीदारी रहेगी। उनका कहना है कि इस अभियान के जरिए, सड़क हादसों में 25 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने भी अभियान को सड़क सुरक्षा की बड़ी पहल बताया। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस और प्रशासन सड़क हादसों को रोकने के लिए एक विस्तृत योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें ब्लैक स्पॉट सुधारने, अन्य कमियां दूर करने और ऐसे स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन भी शामिल है।

स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पहुंचे ट्रक चालक भी इस पहल से बेहद संतुष्ट नजर आए। पंजाब के हरजिंदर सिंह ने कहा कि व्यस्तता के चलते वह कभी अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवा पाते थे, लेकिन इस शिविर में उन्हें पता चला कि उनका बीपी हाई है और नजर कमजोर है। उन्हें नि:शुल्क चश्मा और दवाइयां दी गई, जिसे वे राहत मानते हैं। वहीं चालक रमेश कुमार ने भी माना कि लंबी दूरी पर वाहन चलाने वाले अधिकतर चालकों को शारीरिक परेशानियों की जानकारी ही नहीं होती और ऐसे शिविर अगर हर टोल प्लाजा पर लगे तो यकीनन हादसों में भारी कमी लाई जा सकती है।

सड़क सुरक्षा को लेकर यह पहला ऐसा अभियान है जिसमें वाहन चालकों की परेशानियों को समझते हुए, राहत, स्वास्थ्य और सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल खड़ा किया गया है जो आने वाले समय में देशभर में नजीर बन सकता है।

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सीएडी सर्किल, कोटा, Website : www.kotamc.org, Email : nnksouth@gmail.com

क्रमांक :- ननिको/दक्षिण/निर्माण/2025/567-581 दिनांक :- 29/07/2025

Notice inviting request for proposal (RFP) : 2025-26

नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से नगर निगम कोटा दक्षिण में कन्सलटेन्ट/पेनल के गठन हेतु कुल निम्न कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। संवेदक निविदा प्रपत्र नगर निगम कोटा दक्षिण की वेबसाईट http://kotamcsouth.org.com, www.urban.rajasthan.gov.in/nnks, http://sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in, से प्राप्त कर सकेंगे।

निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 01.08.2025 से 14.08.2025 तक
निविदा की धरोहर राशि, निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क व तकनिकी बिड के दस्तावेज ऑन-लाईन अपलोड करने की तिथि : 01.08.2025 से 14.08.2025 तक
प्री-बिड मिटींग की तिथि : 07.08.2025 (प्रातः 11:00 बजे) (अधीक्षण अभियन्ता कक्ष)
निविदा खोलने की तिथि : 18.08.2025 (प्रातः 11:00 बजे)

क्र. सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस	समयावधि
1	Preparation of DPR & BoQ including architecture and structural and design sevices with details planning. (i) Commercial Complex/ Other Building/ Facad Development/ Parks/ Land Scapina/ Beautification Projects.	25000/-	1500/-	500/-	12 माह
2	Preparation of DPR & BoQ including architecture and structural and design services with details planning. (i) Chouraha Geo-Metrical Desgin/ Sports Ground/ Roads/ Small Bridge.	25000/-	1500/-	500/-	12 माह
3	Preparation of DPR & BoQ including architecture and structural and design services with details planning. (i) Community/ Shamshaan/ Toilets	25000/-	1500/-	500/-	12 माह
4	Preparation of 3D Model of proposed schemes/ Building/ Chauraha etc. (i) Computer Genrated Model/ 3D View (All Sides)/ Walk Through.	25000/-	1500/-	500/-	12 माह

अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम कोटा दक्षिण

राज.संवाद/सी/25/7678

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से जनसुनवाई बनी सुशासन की नई मिसाल

मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। शासन को सेवा का माध्यम मानते हुए यह सरकार प्रदेशवासियों के हित के लिए पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं संवेदनशीलता के साथ पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा नियमित रूप से की जा रही जनसुनवाई भी इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।

- **जयराम और कैलाश को मिला कृषि विद्युत कनेक्शन**
- **मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद, अब नहीं सूख रही फसलें**

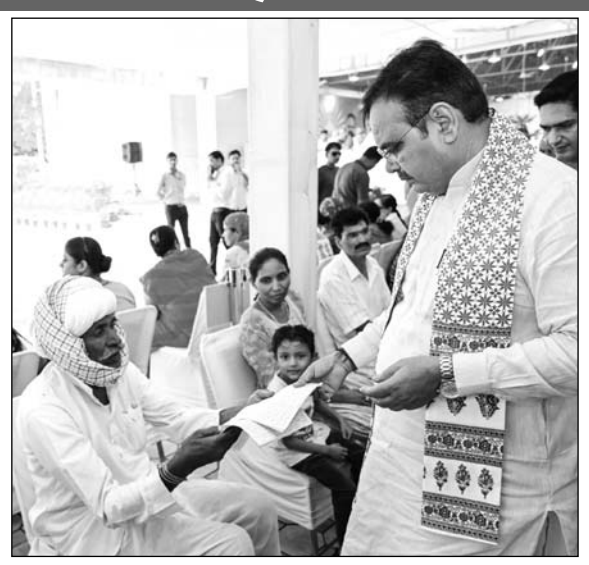

मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में समस्या का समाधान किया।

जनसुनवाई में फरियादी नगर निगम, जेडीए, गृह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। कोई परिवादी बीमारी में इलाज की मदद के लिए आते हैं तो कोई परिवादी अपनी पेंशन से जुड़े प्रकरण को निस्तारण के लिए तो कोई विद्युत कृषि कनेक्शन के लिए। मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं जिससे आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

कोटपूतली के नारायणपुर तहसील निवासी जयराम किसान परिवार से हैं। उन्होंने कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था जोकि पिछले काफी समय से लंबित था। जनसुनवाई में अपने इस प्रकरण को लेकर जब जयराम आए तो मुख्यमंत्री ने फसलों के सीजन को देखते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जयराम के कृषि कनेक्शन आवेदन को प्राथमिकता से लेते हुए कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। इसी तरह अलवर की लक्ष्मणगढ़ तहसील के कैलाश चंद मीणा को भी कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में फसलों की सिंचाई नहीं होने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जनसुनवाई में मुख्यमंत्री को अपनी इस परेशानी से अवगत कराया।

नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा व स्टाफिंग में खामियों को लेकर नोटिस जारी

आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी

जयपुर/जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एस. भाटी और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा शामिल हैं, ने देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा, स्टाफिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर खामियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नवोदय विद्यालय समिति को नोटिस जारी किया है। यह याचिका अधिवक्ता विनीत आर. दवे द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कई नवोदय विद्यालयों में अब तक पूर्णकालिक वार्डन, काउंसलर, सीसीटीवी निगरानी, परिधि सुरक्षा, आपात प्रबंधन और शिकायत निवारण तंत्र जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। जबकि शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, एनसीपीसीआर, एनडीएमए द्वारा इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कई चौंकाने वाले तथ्य को उजागर किया है जैसे कि दिसम्बर 2024 की शिक्षा के क्षेत्र में संसद की स्थासी समिति को भी उद्धृत किया है जिसके अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय में 6800 से भी अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली पड़े है। यानी इन विद्यालयों में 24.77 प्रतिशत पदो की रिक्तियों को भरा नही गया है जबकि कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि रिक्तियों को जल्द भरा जाये। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 2019 में जारी एक परिपत्र के माध्यम से सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों को एमटीएस के रूप में छात्रावासों की देखरेख के लिए नियुक्त करने का निर्देश दिया गया, जो केवल औपचारिकता रह गया है और योग्यता आधारित स्टाफिंग के मापदंडों का उल्लंघन करता है।

- **जवाहर नवोदय विद्यालय में 6800 से भी अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली पड़े है**
- **विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे अधारभूत ढ़ांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है**

इसके अतिरिक्त, याचिका में यह भी ज़ोर दिया गया है कि विगत वर्षों में नवोदय विद्यालयों में आत्महत्याओं सहित कई छात्र मौतों की घटनाएं सामने आई हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी और छात्रावासों में अपर्याप्त निगरानी की ओर इशारा करती हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी। आरटीआई से ही प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 से 2017 के बिच ही इन विद्यालयों में 49 छात्रो ने आत्महत्या की, जिसमें से आधे एसएसी -एसटी वर्ग के थे। वही 2019 से 2023 के बीच 25 छात्रो ने आत्महत्या की, जिसमें भी एक बड़ा हिस्सा एसएसी -एसटी वर्ग का था। याचिकाकर्ता का कहना है कि ज्यादातर इन मौतों में कई मामलों में एफआईआर दर्ज है परन्तु कई मामलों में मौत का कारण स्पष्ट नही हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस बात से नकारा नही जा सकता कि इन विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे अधारभूत ढ़ांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है, और आये दिन इन मुदो पर प्रदर्शन किये जाते हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं।

कुमावत को एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड-हॉक कमेटी के कन्वीनर के तौर पर दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति करने पर सहकारिता रजिस्ट्रार, आरसीए और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता मधुसुदन सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता क्रिकेट संघ की वर्तमान कार्यकारिणी को साल 2022 से 2026 के लिए चुना गया था। दीनदयाल कुमावत अपने आप को सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने का दावा करते हैं। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अन्य याचिका लंबित है। याचिका में कहा गया कि सहकारिता विभाग ने गत 27 जून को दीनदयाल कुमावत को आरसीए की एड-हॉक कमेटी का कन्वीनर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। एड-हॉक कमेटी का कंवीनर वह व्यक्ति ही बन सकता है, जो आरसीए चुनाव लडने के लिए पात्र हो। दीन दयाल कुमावत का सवाई माधोपुर से कोई रिश्ता ही नहीं है। वे ना तो सवाई माधोपुर में जन्मे और ना ही वहां निवास करते हैं। वे सवाई माधोपुर के किसी प्राइमरी क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी भी नहीं है। ऐसे में वे जिला संघ के किसी पद के लिए भी पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाया गया है। इसलिए उनके नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

विवाद बढ़ा तो ठेकेदारों ने 20 प्रतिशत रेट घटाकर ले लिया पौधे सप्लाई का टैंडर

- कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ग्रेटर निगम में पौधे सप्लाई के टैंडर में भारी गड़बड़झाला चल रहा हैं। "वन टाइम प्लांटेशन" के लिए 10 फ़ीट पौधे देने के लिए ठेकेदारों ने पहले तो मात्र 5 प्रतिशत कम रेट डाली थी, परन्तु हैरिटेज निगम में 55 प्रतिशत कम दर आने के बाद जब विवाद बढ़ा तो इन्ही फर्मों ने अपनी रेट 20 प्रतिशत तक घटाकर काम ले लिया।

अब चर्चाएं यह हो रही है कि आखिर हैरिटेज निगम से 35 फ़ीसदी ज्यादा कीमत पर पौधे खरीदने के लिए ग्रेटर निगम के अफसर उत्सुक क्यों है? वह भी उस स्थिति में जब अधिकांश ठेके एक ही फर्म मैसर्स जसवाल बिल्डर्स के नाम पर छूटे है। हालाँकि उद्यान शाखा के अफसरों का कहना है कि 50 से 55 प्रतिशत कम राशि पर पौधे उपलब्ध करवाना संभव ही नहीं है। परन्तु सवाल यह उठ रहा है कि यह चिंता तो कम दर पर ठेके लेने वाले संवेदक को होनी चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर निगम प्रशासन ने वन टाइम प्लांटेशन कि निविदा के कार्यादेश "नेगोशिएशन" के बाद 20 प्रतिशत कम दर पर जारी किये है। यहाँ ठेकेदार ने 300 रुपए के 10 फीट के पेड़ 270 से 285 रुपए तक में देने की दर डाली थी, परन्तु जब हैरिटेज निगम में आधी कीमत यानी कि 135 से 150 रुपए तक की रेट आयी तो बड़ा विवाद हो गया। तमाम विवादों के बावजूद ग्रेटर निगम प्रशासन ने यह कार्यादेश जारी करने का फैसला लिया। मजेदार बात यह है कि जेडीए प्रशासन ने भी यही पेड़ ठेकेदारों से 160 से 170 रुपए के बीच खरीदे है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे है कि आखिर ग्रेटर निगम प्रशासन ही जानबूझकर लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान क्यों झेलने पर उतारू है। जबकि तीनों विभागों ने पौधों की एक समान खरीद दर 300 रुपए तय की थी। जिसमें नीम, शीशम, करंज, गुलमोहर, अमलतास, अशोक, चंपा, आंवला, सीताफल, खेजड़ी, अर्जुन, बालम खेड़ा, कनेर, हरसिंगार, शहतूत, अमरूद, पीपल, जामुन, बेलपत्र, गुड़हल, मौलश्री, चंदन और आम के पेड़ शामिल है।

सूत्रों की माने तो ग्रेटर नगर निगम की उद्यान शाखा ने इस बार "वन टाइम प्लांटेशन" के 30 लाख रुपए से कम के टेंडर में भी कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दी थी, जिसके कारण "डी" श्रेणी के ठेकेदार चाहते हुए भी इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस कारण इन निविदाओं में सिर्फ चुनिंदा फर्मों ने ही भाग लिया।

भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करे सरकार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को कहा है कि वह भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कानून की समीक्षा करे और जरूरत पडने पर उन्हें संशोधित करने पर विचार करे। अदालत ने कहा कि ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे को मजबूत करने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसे अनूठी परिस्थिति में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश सेहर गोगिया के अपने पिता के जरिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निर्वासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता**
- **याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निर्वासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता**

अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निर्वासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

याचिका में कहा गया कि उसके माता-पिता का मार्च, 2018 में विवाह हुआ था। इसके बाद वे आस्ट्रेलिया गए थे। जहां 1 जून, 2020 को याचिकाकर्ता का जन्म हुआ। इस पर वहां की सरकार ने नवंबर, 2021 में याचिकाकर्ता को नागरिकता दे दी। इसके बाद वह भारत सरकार से वीजा लेकर अपने माता-पिता के साथ यहां आ गई। इस दौरान उसकी समय-समय पर वीजा अवधि 24 जनवरी, 2024 तक बढ़ाई गई। याचिका में कहा गया कि इस बीच याचिकाकर्ता के माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद पैदा हो गया और उसकी मां ने याचिकाकर्ता के पिता पर कई केस कर दिए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से इमिग्रेशन ब्यूरो में याचिकाकर्ता की वीजा अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया, जिसे ब्यूरो ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसकी मां ने वीजा अवधि बढ़ाने के लिए एनओसी नहीं दी। ऐसे में याचिकाकर्ता को आशंका है कि उसे अवैध प्रवासी मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मामले में कोर्ट दखल देकर उसकी वीजा अवधि बढाए। इसका विरोध करते हुए इमिग्रेशन ब्यूरो की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से अभी तक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी विभाग याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या उसे डिपोर्ट नहीं कर रहा है। ब्यूरो की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता आस्ट्रेलिया की नागरिक है और उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए।

देवनानी ने लोकसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट की

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को नई दिल्ली की एक दिवसीय यात्रा के दौरान संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। देवनानी की बिरला से संसदीय विधायी मामलों, विधान सभा के आगामी सत्र के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा विधायी कार्यों की गुणवता को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। देवनानी ने संसदीय मामलों के संबंध में बिरला से मार्गदर्शन भी लिया। देवनानी ने बिरला को राजस्थान विधानसभा की वर्तमान गतिविधियों, नवाचारों और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों की विस्तार से जानकारी दी। देवनानी ने लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि राजस्थान विधान सभा अपनी स्थापना का अमृत महोत्सव मनायेगी। विधान सभा गठन के 75वें वर्ष में प्रवेश के साथ अमृत महोत्सव के शुभारम्भ की रूप रेखा तैयार की जा रही है। देश की श्रेष्ठ विधानसभाओं में शुमार राजस्थान विधान सभा को लोकतंत्र का जीवन्त स्थल बनाने के लिए नये कदम उठाये जा रहे है। बिरला से राजस्थान विधान सभा के सदन को पेपर लैस किये जाने के संबंध में आ रही कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग किये जाने का अनुरोध किया। बिरला ने संबंधित अधिकारियों को राजस्थान विधान सभा के नेवा प्रोजेक्ट की कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश दिए। बिरला ने देवनानी को नेवा प्रोजेक्ट के संबंध में लोकसभा से हर सम्भव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। देवनानी ने बिरला को राजस्थान विधान सभा परिसर में बनाई गई कारगिल शौर्य वाटिका की जानकारी दी।

- **देवनानी की बिरला से संसदीय विधायी मामलों पर चर्चा**

देवनानी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस पर राजस्थान विधान सभा में कारगिल शौर्य वाटिका में वीरांगनाओं द्वारा पौधारोपण किया गया। बिरला ने राष्ट्र के शौर्य के लिए विधान सभा द्वारा किये गये इस नये कदम की सराहना की। 75 वर्षों के गौरवशाली डिजिटल म्यूजियम को प्रतिदिन लोग देखने आ रहे है प्रतिदिन आमजन बढी संख्या में देखने आते हैं। उन्होंने इतिहास को रेखांकित करते हुए निकट भविष्य में आयोजित होने वाले विधानसभा से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी बिरला से साझा की।

मुख्यमंत्री ने दी भूमि आवंटन की स्वीकृति

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में विद्युत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

- **जैसलमेर के फूसासर में 765 के.वी. में स्थापित होगा विद्युत उपकेन्द्र**

सरकार द्वारा बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं।

इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने जैसलमेर जिले की भणियाणा तहसील के फूसासर में 765 के.वी. के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा यह विद्युत उपकेन्द्र 80 हैक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का यह निर्णय पश्चिमी राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस उपकेन्द्र की स्थापना से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा आमजन को सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

भाजपा रक्षाबंधन पर्व को सेवा, संगठन और समर्पण के रूप में मनाएगी

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी आगामी 8 से 10 अगस्त तक पूरे राजस्थान में रक्षाबंधन पर्व को जनसहभागिता, संगठनात्मक सहभागिता एवं सामाजिक समर्पण के साथ भव्य रूप में मनाने जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता "रक्षा का यह पर्व, सामाजिक एकता और सेवा का अवसर" के मूलभाव के साथ जिलों, विधानसभाओं और मंडलों में समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाएंगे।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान संयोजक मुकेश दाधीच ने बताया कि प्रत्येक जिले में एक जिला महामंत्री एवं महिला मोर्चा की दो पदाधिकारी संयोजक व सह-संयोजक के रूप में कार्यक्रम का संचालन करेंगी।

8 अगस्त को सम्मान व समर्पण दिवसः

इस दिन पार्टी कार्यकर्ता ट्रैफिक पुलिस, अस्पताल स्टाफ, विद्यालयों, सरकारी व निजी कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों सहित सेवाभावी कर्मियों को राखी बांधकर आभार प्रकट करेंगे। बहनों द्वारा तिलक, राखी एवं मिष्ठान वितरण कर यह संदेश दिया जाएगा - आप हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। स्थानीय मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से इस सेवा भावना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

9 अगस्त को संगठनात्मक एकता व परिवार दिवस पर भाजपा कार्यकर्ता इस दिन अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे और बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन के सदस्यों के बीच भाईचारे का पर्व मनाकर भाजपा परिवार - एक सूत्र में बंधा, संकल्पित भारत के लिए समर्पित भाव को सशक्त करेंगे।

10 अगस्त को सेवा व सामाजिक सद्भाव दिवस को भाजपा कार्यकर्ता सीमाओं पर तैनात सैनिकों को राखी भेजेंगे या उनके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। साथ ही कच्ची बस्तियों, मजदूर बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ियों और घुमंतू समाज के बीच जाकर राखी व मिठाई वितरित की जाएगी। यह दिन "रक्षा का धागा, सम्मान और अपनत्व का संदेश" लेकर सेवा और संवेदना का उत्सव बनेगा।

यह आयोजन सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों की सहभागिता से जिले, विधानसभा एवं मंडल स्तर पर आयोजित होंगे। पूर्व तैयारी बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।

भाजपा का उद्देश्य रक्षाबंधन को सेवा, संगठन और समर्पण के पर्व के रूप में जन-जन तक पहुँचाना है।

रक्षा सूत्र से बंधेगा भारत, एकता, सेवा और संस्कारों के साथ - यही है इस कार्यक्रम की मूल भावना।

आराध्य देव गोविंद देव जी को कच्चे सूत की केसरिया रंग की पवित्राएं अर्पित की

जयपुर। श्रावण शुक्ला द्वादशी बुधवार को आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में ठाकुर गोविंद देव जी, राधा रानी और अन्य विग्रहों को पवित्रा धारण कराई गई। ठाकुर श्रीजी को सुनहरी, रुपहली, 108 मणियों की रेशमी पवित्रा, कच्चे सूत की केसरिया रंग की पवित्राएं तथा 108 गांठों वाली पीले-केसरिया सूत की विशेष पवित्राएं अर्पित की गईं।

चमकीले रेशम से बनी दो मुख्य पवित्राएं ठाकुर जी की पोशाक के ऊपर धारण करवाई गईं जबकि पांच विशेष पवित्राएं चरणों में समर्पित की गईं। मंदिर के जगमोहन में सजे चांदी के झूले पर 216 पवित्राएं बांधी गईं।

धूप झांकी से लेकर शयन झांकी तक ठाकुर जी ने पवित्रा धारण किए रखा। गौड़ीय संप्रदाय में पवित्रा को वर्ष भर की गई सेवा का प्रतीक माना जाता है। यदि पवित्रा अर्पित नहीं की जाती, तो वर्ष भर की सेवा निष्फल मानी जाती है। पवित्रा सुंदर, सुगंधित केसर से रंगी हुई होती है जिसकी गांठें भगवान को कष्ट न दें, बल्कि उन्हें शोभायमान करें।

इस अवसर पर गोविंद देव जी के प्राकट्ययकर्ता रूप गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि का पूजन भी श्रद्धा से किया गया। श्रीमन् चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन् नित्यानंद महाप्रभु, श्रीमन् नित्यानंद महाप्रभु, श्रीमन् गदाधर पंडित, श्रीनिवास जी, अद्वैताचार्य जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, श्रीजीव गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, पद्म कुमार गोस्वामी जी सहित गौड़ीय संपदाय के 64 आचार्यों का वेद मंत्रोच्चार के साथ भाव भरा आ ान कर पूजन किया गया।

सभी के चित्रपट के समक्ष पत्तल में मिठाई, सब्जी-पूड़ी सहित अन्य व्यंजन परोसे गए। उल्लेखनीय है कि गौड़ीय संप्रदाय की वंश परम्परा में सातों देवालयों के करीब 200 आचार्य हुए हैं।

शिक्षा के साथ संस्कारों की सीख दे रहा है गायत्री परिवार: दिलावर

जयपुर। किरण पथ, मानसरोवर स्थित गायत्री वेदना निवारण केंद्र परिसर में मां भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रवेशोत्सव- 2025 बुधवार को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे। उन्होंने मां गायत्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिलावर ने कहा कि गायत्री परिवार के इस विद्यालय ने बहुत कम समय में अच्छी तरक्की की है। यह विद्यालय शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी प्रदान कर रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि विद्यालय का शुभारंभ मेरे द्वारा हुआ था तथा आज प्रवेश उत्सव भी मेरी उपस्थिति में हो रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए उन्होंन कहा कि गायत्री परिवार सामाजिक एवं राष्ट्रिहत के कामों में सदा अग्रणी रहता है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि गायत्री परिवार सदैव समाज एवं राष्ट्र के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजकीय विद्यालय में बड़ी तेजी से नामांकन मे वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए गुणात्मक प्रयास एवं नवाचारों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। बच्चों ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ शिक्षा मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। शिक्षा मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने बच्चों को स्कूल बैग, स्टेशनरी सहित अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की।

गायत्री परिवार के मां भगवती विद्यालय के नव प्रवेशित छात्रों का प्रवेश उत्सव मनाया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी एवं राजस्थान जोन समन्वयक ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि यह विद्यालय गायत्री परिवार द्वारा नि:शुल्क संचालित किया जा रहा है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय में बच्चों को पाठ्य सामग्री, पोशाक एवं आवश्यक सुविधाएं गायत्री परिवार एवं समाजसेवी भामाशाहों के सहयोग से नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड 69 पार्षद आशीष शर्मा, वार्ड 70 के पार्षद रामावतार गुप्ता, वार्ड 72 के पार्षद पारस जैन तथा भाजपा मानसरोवर मंडल अध्यक्ष विपिन सिंघल उपस्थित रहे। ट्रस्टी सतीश भाटी, डॉ. प्रशांत भारद्वाज, केंद्र के व्यवस्थापक आर. डी. गुप्ता ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया।

जयपुर स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ. निधि पटेल ने की समीक्षा बैठक

जयपुर। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ डॉ निधि पटेल ने बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ निधि पटेल ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि स्मार्ट सिटी में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कैमरों से कचरा फेंकने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएं।

जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ डॉ. निधि पटेल ने बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक की।

जिससे कि सड़क पर कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएं। सीईओ निधि पटेल ने कहा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि शहर के प्रमुख बाजारों में देर रात तक खुलने वाली दुकानों से कचरा सड़क पर ही फेंका जा रहा है, जो कि सुबह तक सड़क पर ही पड़ा रहता है और ओपन डिपो का रूम लेकर शहर की सफाई व्यवस्था को खराब कर रहा है। इसके लिए निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के अधिकारी मिलकर ठोस प्लानिंग करें और उन दुकानों को चिह्नित कर समझाइश करें नहीं मानने पर भारी चालान वसूला जाएं। जिससे कि सफाई व्यवस्था बेहतर हों।

वहीं समीक्षा बैठक के दौरान सीईओ निधि पटेल ने स्मार्ट सिटी के प्रगतिरत प्रोजेक्ट की समीक्षा की और कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही लाल डूंगरी कचरा ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण कार्य, एमआरएफ प्लांट के शुरू होने के लिए शीघ्र पॉल्यूशन एनओसी लेने और लंगड़ियावास में पौधरोपण करने के निर्देश दिए।समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी के अधिकारी और नगर निगम हेरिटेज के जोन उपायुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

बाजारों में कचरा संग्रहण के लिए चल रहे निगम के हूपर, व्यापारी हूपर में ही डालें कचरा वहीं, सीईओ डॉ निधि पटेल ने कहा कि नगर निगम हेरिटेज की ओर से समयानुकूल सभी बाजारों में हूपर चल रहे है। दुकानदार अपने कचरे को हूपर में ही डालें, सड़क पर कचरा नहीं फैलाएं, जिससे कि सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हों।

रक्षा सूत्र कार्यक्रम में डॉ. सतीश पूनियां को आदिवासी बहन-बेटियों ने राखी बांधी

सतीश पूनियां ने हजारों आदिवासी माता-बहनों के साथ राखी का पर्व मनाया

जयपुर/डूंगरपुर। मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के आदिवासी अंचल के डूंगरपुर जिले में रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में रक्षा सूत्र कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सकारात्मक तौर पर भाजपा की वागड़ क्षेत्र में मजबूती के तौर पर चर्चाओं में है। इस ऐतिहासिक रक्षा सूत्र कार्यक्रम में शामिल होने भाजपा हरियाणा संगठन प्रभारी डॉ. सतीश पूनियां राजस्थान के वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर पहुंचे, जहां काफी संख्या में जनजाति माता-बहनों ने उन्हें राखी बांधकर उनके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और उन्नित का आशीर्वाद दिया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भाजपा पूर्व प्रदेश महामंत्री, पूर्व राज्यमंत्री सुशील कटारा द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित रक्षासूत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एक हजार से अधिक बहनों ने सतीश पूनिया एवं सुशील कटारा को राखी बांधी। कार्यक्रम मे सागवाडा विधायक शंकरलाल डेचा, जिलाध्यक्ष अशोल पटेल, सभापति अमृत कलासुआ, पूर्व महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अल्का मूंदड़ा इत्यादि नेता व कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे।

- **डूंगरपुर में रक्षा सूत्र कार्यक्रम में माता-बहनों ने डॉ. सतीश पूनियां को अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और उन्नित का आशीर्वाद दिया**

डॉ. सतीश प्पूनियां ने संबोधित करते हुये कहा कि, पहले बेटियों को अभिशाप की तरह मानते थे, किसी जमाने में बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, लेकिन मैं यह मानता हूं जिसने पिछले जन्म में अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, उनको बेटी नसीब होती है। मैं खुशनसीब हूं क्योंकि बेटी एक पिता का सबसे बड़ा संबल होती है। उन्होंने कहा कि, एक बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो दुनिया के बड़े-बड़े आशीर्वाद फीके पड़ जाते हैं, एक मां भले ही उम्रदराज होगी मैं भी देखता हूं कि मेरी 95 वर्षीय मां जब मेरे सिर पर हाथ फेरती हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया की सल्तनत मुझे मिल गई, मातृशक्ति किसी भी रूप में हो, जब मैं चुनौतियों से लड़ता था मेरे घर का चूल्हा जलाने का काम और विपरीत परिस्थितियों में मेरे पीछे डटकर खड़े होने वाली कोई थी वह मेरी धर्मपत्नी थी।

पूनियां ने कहा कि,दुनिया में वह हमारा आदिवासी समाज है जो जल जंगल और जमीन की रक्षा करता है, दुनिया ने यह नारा बहुत देर से लगाया लेकिन हमारा आदिवासी समाज सदियों से प्रकृति और संस्कृति का संरक्षण करता आया है, राजस्थान और हिंदुस्तान का इतिहास है कि पेड़ों के रक्षा के लिए अमृता देवी शहीद हो गईं, यह वर्षों पुरानी परंपरा है। मुझे सुखद अनुभूति और बहुत खुशी हुई कि हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटियां पढ़ लिखकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं, और इन्हीं आदिवासी माता बहनों का आज रक्षा सूत्र कार्यक्रम में राखी के रूप में मुझे जो आशीर्वाद मिला वह मुझे नई ऊर्जा और ताकत के साथ कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है।

भाजपा हरियाणा संगठन प्रभारी डॉ. सतीश पूनियां को डूंगरपुर में जनजाति माता-बहनों ने राखी बांधकर आशीर्वाद दिया।

फरार हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे शातिर बदमाश और हिस्ट्रीशीटर कुंदन जाट को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया है कि आरोपी कुंदन जाट थाना सदर क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है और गंभीर वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया है की बीती 10 जुलाई को सरसिया निवासी नरेश कुमार मीणा आनन्दा होटल पर वेटर का काम कर रहा था। उसी दौरान निलेश बलाई, खाना कीर व 5-6 अन्य आरोपी वहां आए और खाने के बाद भुगतान मांगने पर जातिगत अपमान करते हुए उसके साथ लाठी, डंडों और लात-घूंसे से जानलेवा हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट आने से प्रार्थी लहूलुहान हो गया। आरोपी जाते-जाते जान से मारने और होटल में आग लगाने की धमकी भी दे गए। इसको लेकर पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला कर जांच शुरू की, जिसके बाद एक आरोपी खाना उर्फ कन्हैयालाल कीर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। वहीं आरोपी कुंदन जाट फरार था। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर मुखबिरों की मदद से कुंदन की लोकेशन ट्रेस की और सदर थाना पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल किया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस टीम में पुलिस उपाधीक्षक रविंद कुमार सहित थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीणा शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुंदन जाट एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पुलिस थाना सदर में 11 संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और थाने का घोषित हिस्ट्रीशीटर है।

पुलिस ने शातिर बदमाश कुंदन जाट को गिरफ्तार किया।

प्ले स्कूल की बिल्डिंग में आग लगी, बड़ा हादसा टला

अजमेर, (कासं)। धोलाभाटा क्षेत्र में मेयो कॉलेज के पीछे पावर हाउस के पास एक निजी प्ले स्कूल में तीसरी मंजिल पर बुधवार सुबह साढ़े दस बजे अचानक आग लग गई। आग लगने से चंद मिनटों में पूरी बिल्डिंग में घने धुएं से भर गई। उस समय नन्हे-मुन्ने बच्चे क्लास रूम में बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ ही देर में धुआं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में फैल गया। धुएं की वजह से कक्षाओं में बैठे बच्चों की चीख-पुकार मच गई और स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। जी प्लस श्री आवासीय मकान में प्ले स्कूल संचालन किया जा रहा है। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई भी बच्चा हताहत नहीं हुआ। सभी बच्चे और स्कूल स्टाफ सुरक्षित है। सूचना पर करीब 10 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंच गई और आग पर काबू पाया।

- **हादसे के समय नन्हे-मुन्ने बच्चे क्लास रूम में बैठकर खाना खा रहे थे**
- **कुछ ही देर में धुआं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में फैल गया**
- **गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई भी बच्चा हताहत नहीं हुआ, सभी सुरक्षित**

जानकारी के अनुसार स्कूल की तीसरी मंजिल पर स्कूल संचालक का आवास है। उनका कहना है कि घर के मंदिर में कथित शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। इमारत में वेंटिलेशन सीमित होने से धुआं तीव्र गति से निचली मंजिलों तक आने से कई बच्चों के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था, कुछ रोने लगे तो कुछ घबराहट में अपने बैग और टिफिन छोड़कर बाहर की ओर भागे। स्कूल स्टाफ ने बच्चों को तुरंत कक्षाओं से सुरक्षित बाहर निकाला और पास के एक मकान में शिफ्ट किया। इसी बीच सूचना मिलते ही दो दमकलें मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने ऊपरी मंजिल पर लगी आग पर काबू पाया। स्कूल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बच्चों की मदद के लिए आस पास रहने वाले लोग भी पहुंच गए और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।

खबर मिलते ही अभिभावक बदहवास हालत में स्कूल की ओर दौड़ पड़े। कई लोग अपने बच्चों का नाम पुकारते हुए गलियारों में उन्हें तलाशते दिखे। एक महिला अभिभावक ने अपने बच्चे को सकुशल देखकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि स्कूल से हमारा घर काफी दूर है। जैसे ही आग की बात सुनी तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाथ कांपने लगे। रास्ते भर सिर्फ यही डर था कि बच्चे के पास कब तक पहुंच पाऊंगी। कई परिजनों ने राहत की सांस लेते अपने-अपने बच्चों को गले लगा लिया। हैरानी की बात यह ही कि स्कूल प्रबंधन का रवैया अभिभावकों के प्रति रूखा नजर आया।

बिल्डिंग मलिक डॉ. रंजीता तंवर का कहना है कि बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर घर है। शॉर्ट सर्किट होने पर आग मंदिर में लग गई थी, जिससे तुरंत भागते हुए नीचे पहुंची और स्कूल के सारे बच्चों को बाहर निकालकर पास के कैंपस में भिजवा दिया था। स्टाफ को भी बाहर निकाल गया, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। घर के अंदर नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया था।

डीडवाना में मिलावटी खाद्य सामग्री पर कार्रवाई

डीडवाना, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर आमजन को शुद्ध एवं गुणवतापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएं जाने के लिए अभियान के तहत रक्षाबंधन त्योहार को मद्देनजर रखते हुए जिले में कारवाई जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को डीडवाना में जिला रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुल्हार, प्रवर्तन निरीक्षक विरेंद्र जाखड़ व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल की संयुक्त टीम ने रिलायंस मॉल, मित्तल सेल्स, आधार मार्ट व समृद्धि बाज़ार का निरीक्षण कर खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन, साफ-सफाई एवं खाद्य सामग्री पर पैकेजिंग तिथि तथा उपयोग दिनांक की जांच की।

इस दौरान मॉल मित्तल सेल्स एवं रिलांयस स्टोर से अवधिपार खाद्य सामग्री जैसे गेहूं का आटा, बिस्कुट, मिक्स सूप, पापड़, हल्दी आदि मिली जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया तथा फर्म को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 32 का इम्प्रूव नोटिस दिया गया। वहीं काजू, किशमिश, अंजीर व बादाम के नमूने एवं मेसर्स रिलायंस मॉल से घी का नमूना और श्री बालाजी दूध एंड मावा भंडार से 10 लीटर दही नष्ट करवाया गया और घी का नमुना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

ऑपरेशन के दौरान बच्चे की किडनी निकालने का आरोप

भरतपुर, (निसं)। यूपी में एक तीन साल के बच्चे के पेट का ऑपरेशन के दौरान किडनी निकाल ली गई। ऑपरेशन के नौ महीने बाद पेट में दर्द की शिकायत होने पर जब बच्चे को अलवर और जयपुर के हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि उसकी किडनी ही गायब कर दी गई।

- **तीन साल के बच्चे के पेट का ऑपरेशन मथुरा में हुआ था, ऑपरेशन के दौरान किडनी निकाली**
- **नौ महीने बाद पेट में दर्द की शिकायत होने पर जब बच्चे को अलवर और जयपुर के हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि किडनी ही गायब कर दी**

मामला मई 2024 का है, जब मयंक का ऑपरेशन मथुरा के केडी मेडिकल हॉस्पिटल में किया गया था। परिवार डीग जिले के कैथवाड़ा का रहने वाला है। पिता भीमसिंह ने बताया कि बेटे को इंफेक्शन ओर खांसी है। ऐसे में उसका इलाज भरतपुर के जनाना हॉस्पिटल में चल रहा है। पिता का कहना है कि जब उन्हें पता चला कि बेटे की किडनी निकाल ली गई है तो मथुरा में कई अधिकारियों को शिकायत दी। जब कार्रवाई नहीं हुई तो हॉस्पिटल के खिलाफ उपभोक्ता मंच में याचिका लगाई है।

पिता भीम सिंह ने बताया उनके बेटे मयंक के पेट में गांठ थी। इस पर उसे मथुरा के केडी मेडिकल हॉस्पिटल में दिखाया। यहां ऑपरेशन के लिए कहा गया। 30 मई 2024 को ऑपरेशन करवाया गया। इस दौरान करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आया। इस ऑपरेशन के 3 दिन बाद बेटे को छुट्टी दे दी गई थी। पेट दर्द होने पर पता चला किडनी गायब है। नौ महीने तक सब कुछ सही चल रहा था। फरवरी 2025 में मयंक के पेट में अचानक दर्द शुरू होने लगा। इस पर उसे अलवर के हरीश हॉस्पिटल लेकर आए। यहां डॉक्टर्स को ऑपरेशन के बारे में बताया गया। यहां ऑपरेशन से पहले हुई सिटी स्कैन की रिपोर्ट दिखाई। इसके बाद वहां अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाई गई, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि पेट में लेफ्ट साइड में किडनी नहीं है। पिता ने बताया कि यकीन नहीं हुआ तो जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल गए। यहां रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन से पहले दोनों किडनी थी लेकिन इसके बाद किडनी निकाल ली गई।

भीम सिंह ने बताया कि अलवर और जयपुर में दोनों डॉक्टर्स की जांच में पता चला कि बेटे की किडनी निकाल दी गई है। इसके बाद दोबारा मथुरा के केडी हॉस्पिटल पहुंचा। यहां जब मैंने उन्हें बताया कि ऑपरेशन के दौरान मेरे बेटे की किडनी निकाल ली है तो धमकाया गया। वहां से मुझे भगा दिया। इसके बाद मैंने वहां सभी अधिकारियों से हॉस्पिटल को लेकर शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर 5 महीने पहले मार्च 2025 में मथुरा के कंज्यूमर कोर्ट में हॉस्पिटल के खिलाफ याचिका लगाई है। पिता ने बताया कि अभी इस मामले में केस चल रहा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भीम का कहना है कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। वह गांवों में जाकर सब्जी बेचता है। एक 8 महीने की बेटी भी है। मयंक की हालात वैसे अभी सही है लेकिन खांसी का इलाज भरतपुर के जनाना हॉस्पिटल में चल रहा है। बच्चे का इलाज करने वाली डॉ. चित्रा गुप्ता ने बताया कि मयंक के पिता ने मुझे रिपोर्ट दिखाई थी। एक रिपोर्ट जो ऑपरेशन के पहले की थी उनमें दोनों किडनियां थीं। रिपोर्ट में ये सामान्य भी नजर आ रही है, लेकिन, दूसरी रिपोर्ट में बच्चे की किडनी गायब थी। जहां किडनी होती है, वहां बाहर की तरफ टांके भी लगे हुए थे।

सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि एक किडनी पर बच्चा या कोई व्यक्ति महिला आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। हालांकि जिसके एक किडनी होती है वह उसके लिए खाना-पीने का ध्यान, संक्रमण से दूर रहना पड़ता है।

मीरा महोत्सव का समापन

मेड़ता सिटी, (निसं)। 521वें मीरा जयंती महोत्सव का रजत रेवाड़ी की शोभायात्रा निकालकर समापन किया गया। मीरा महोत्सव समिति के सचिव रविप्रकाश कमेडिया ने बताया कि रजत रेवाड़ी चारभुजानाथ मंदिर से प्रारंभ होकर सब्जी मंदिर, पड़ाव होते हुये शहर के मुख्य मार्गों से होते पुन: चारभुजानाथ मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। महोत्सव के समापन की पूर्व संध्या पर राजस्थान प्रांत प्रचारक निंबाराम ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं भजन गायक प्रकाश माली ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर विधायक लक्ष्मणराम कलरू, उपखंड अधिकारी पूनम चोयल, तहसीलदार रामसिंह गुर्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष पवन परतानी, महोत्सव समिति अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, श्याम तिवाड़ी, जगदीश नारायण शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोतम टाक, विनोद भाटी, नारायण पारिक, अभिमन्यु शर्मा, रवि गहलोत, कैलाश गौड़, राजू भाई माली सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

मावा कारखाने पर पकड़ा 350 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया

किशनगढ़बास, (निसं)। खैरथल-तिजारा जिले की तहसील तिजारा के गांव हमीरका में चल रहे मावा बनाने के कारखाने पर खाघ सुरक्षा की टीम ने आकस्मिक छापा मारकर 350 लीटर ड्रमों के अंदर भरा मिलावटी दूध पकड़ा और उसे मौके पर ही नष्ट कराकर कारखाने को सील किया है। इस दौरान टीम ने मौके पर निरीक्षण के दौरान मिले रिफाइंड तेल के पीपे, एसएनएफ पाउडर, मिल्क पाउडर के कट्टे बरामद किए हैं। यह कारवाई जिले भर में आगामी त्यौहारों को देखकर जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर शुरू की गई है।

- **टीम ने रिफाइंड तेल के पीपे, एसएनएफ पाउडर, मिल्क पाउडर के कट्टे बरामद किए**
- **जांच के दौरान परिसर में भारी गंदगी मिली और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर परिसर को सील कर दिया**

विभाग की टीम लगातार सैंपलिंग कर मिलावट खोरी करने वालों पर नकेल कसे हुए यह अभियान 9 अगस्त तक चलाया जाएगा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि त्योहार के सीजन में मिठाइयां बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम हमीराका, तहसील तिजारा में छापा मारा। मौके पर आरिफ खान द्वारा मावा बनाने के लिए दूध में मिलावट की जा रही थी। टीम ने मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से मौके पर ही दूध की जांच की, जिसमें आंशिक मिलावट की पुष्टि हुई। छापे के दौरान रिफाइंड तेल के पीपे, एसएनएफ पाउडर, मिल्क पाउडर के कट्टे बरामद किए गए। ये सभी सामग्री दूध में मिलावट और फैट बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। मौके से लिए गए दूध और मावा के नमूने खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं, मिलावटी व बदबूदार दूध को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जांच के दौरान परिसर में भारी गंदगी पाई गई और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते परिसर को सील कर दिया गया। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार, उपनिरीक्षक लोकेश (थाना अधिकारी, शेखपुर अहीर), महिपाल सिंह, सुभाष यादव, रमेश शर्मा, हेमराज, सुंदर सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

एलिवेटेड रोड के पिलर से पिकअप मिनी कंटेनर टकराया

अजमेर, (कासं)। स्टेशन रोड माल गोदाम के सामने बुधवार दोपहर एक पिकअप मिनी कंटेनर एलिवेटेड रोड के पाइलिंग पियर से टकरा गया। कंटेनर के ठीक पीछे चल रहा टैंपो भी अचानक ब्रेक लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। दोनों वाहनों के चालकों के चोटें आई हैं। घटना के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन मंगाकर वाहन को साइड में कराया और यातायात को सूचारू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पियर की क्लीयरेंस हाइट कम है और जगह-जगह ऊंचाई संकेतक-चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ड्राइवर पियर की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा पाते, इसलिए अक्सर ऐसे टच-डाउन हो जाते हैं। लोगों ने बताया कि चालक वाहन को मोड़ने के लिए जैसे ही पियर के करीब आया और एकाएक ऊंचाई का अनुमान नहीं लगा पाया।

परिजनों और ग्रामीणों का प्रदर्शन

बीकानेर, (निसं)। सरकारी स्कूल के लेक्चरर (टीचर) ने 11वीं की छात्रा को लव लेटर दे दिया। छात्रा ने इसकी जानकारी परिजन को दी तो हंगामा हो गया। छात्रा के पेरेंट्स और ग्रामीण बुधवार सुबह स्कूल पहुंचे। स्कूल के गेट को ताला लगाकर प्रदर्शन किया।

हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी किशनदान चारण ने लेक्चरर को सस्पेंड कर दिया। टीचर का मुख्यालय भी डूंगरपुर कर दिया है। मामला खाजूवाला के दंतौर थाना इलाके का है। जानकारी के अनुसार, टीचर ने मंगलवार को छात्रा को लव लेटर दिया था। छात्रा ने इस लव लेटर की सूचना परिजनों को दी। परिजन ने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन को दी। स्कूल ने शाम को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इसकी शिकायत भेजी। वहीं, बुधवार सुबह परिजन और ग्रामीण स्कूल के बाहर पहुंच गए। आरोपी टीचर को निलंबित करने की मांग करने लगे। सुनवाई न होने पर स्कूल का गेट बंद कर ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए। इसके बाद स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स भी वहां पहुंच गए।

स्मार्ट मीटर और निजीकरण के खिलाफ ग्रामीणों व किसानों का प्रदर्शन

पाटन, (निसं)। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने सहायक अभियंता कार्यालय चला पर धरना प्रदर्शन किया। धरने में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों, किसानों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली के निजीकरण, स्मार्ट मीटरों की अनिवार्यता, अघोषित कटौती और क्षेत्रीय समस्याओं के खिलाफ छह सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सभा की अध्यक्षता पूर्व सरपंच बीरबल काजला व जगदीश सैनी ने की, जबकि संचालन ओमप्रकाश सैनी (संयोजक, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति) ने किया।

माकपा सचिव कॉ. गोपाल सैनी ने कहा कि स्मार्ट मीटर गरीब किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा हमला है। इसे अडानी-अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ठेकेदार के कर्मचारी जबरन स्मार्ट मीटर लगाने गांव आए, तो जनता उन्हें वापस लोटा देगी। सभा में वक्ताओं ने मांग की कि जेईएन गुहाला को अनिवार्य रूप से गुहाला जेईएन ऑफिस में बैठने की व्यवस्था की जाए। नांगल पावर हाउस से बार-बार होने वाले फॉल्ट से जनता त्रस्त है, इसलिए गुहाला जीएसएस को चौकड़ी जीएसएस से जोड़ा जाए। रास्तों में खड़े क्षतिग्रस्त बिजली खंभों को भी तत्काल हटाने की मांग की गई। संघर्ष समिति ने 30 अगस्त तक चलने वाले हस्ताक्षर अभियान की घोषणा की है। घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आठ अगस्त को नीमकाथाना ग्रामीण एईएन कार्यालय का घेराव भी प्रस्तावित है।

बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने सहायक अभियंता कार्यालय चला पर धरना दिया।

ओमप्रकाश सैनी और विजय सिंह गजराज के नेतृत्व में 18 सदस्यीय बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का गठन किया गया, जो आगामी आंदोलनों की रणनीति तय करेगी। धरने में कॉ. ओमप्रकाश यादव, रोशन लाल गुर्जर, सुरेंद्र खोखर, फूलचंद सैनी, जेपी वर्मा, गणपत राम मिठारवाल, पवन मील सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। ज्ञापन की मुख्य मांगे जिसमें स्मार्ट मीटर लगाने की योजना रद्द हो, बिजली निजीकरण पर रोक लगे, जेईएन गुहाला को गुहाला जेईएन ऑफिस में बैठने की व्यवस्था हो, गुहाला जीएसएस को चौकड़ी से जोड़ा जाए, क्षतिग्रस्त और रास्ते में खड़े खंभे हटाए जाएं, अघोषित बिजली कटौती बंद हो। धरने में श्रवण यादव, हरिसिंह कुड़ी, कैलाश सैनी, रमेश सैनी, सुरेश सैनी, शिवराम लांबा, सूबेदार रामकुमार आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।

- **प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर को गरीब किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा हमला बताया**

स्मार्ट मीटर लगाने विरोध जारी

डीडवाना, (निसं)। प्रदेशभर में लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को लाडनूं विधायक मुकेश भाकर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया साथ ही कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। विधायक मुकेश भाकर ने उपभोक्ताओं के घरों में जबरन बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हुए कहा कि बिजली कंपनियाँ केंद्र सरकार व राज्य सरकार के इशारे पर स्मार्ट मीटर लगा रही है, जबकि सभी उपभोक्ताओं के घरों में पहले से ही डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि यह कदम अनावश्यक है, जिससे करोड़ों मीटर बर्बाद होंगे और अरबों रुपये के स्मार्ट मीटर लगाकर कंपनियों व ठेकेदारों की जेबें भरी जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर अब खुली छूट को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन किसान वर्ग इसका पूर्ण विरोध करेगा।

चेक अनादरण के मामले में आरोपी दोषमुक्त

तारानगर, (निसं)। तारानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट अजयदीपसिंह की अदालत ने चेक अनादरण के एक मामले में निर्णय पारित करते हुए तारानगर के कस्बे के गांव रेवासी निवासी ताराचंद पुत्र जसूराम को दोषमुक्त कर चेक रिटर्न मेमो के साथ छेड़छाड़ करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता योगेश जैन ने बताया कि परिवादी तारानगर के दिनेश कुमार पुत्र लखनराम द्वारा ताराचंद के विरुद्ध चेक अनादरण का मामला दर्ज करवाया था दोनों पक्षों की साक्ष्य के उपरांत न्यायालय द्वारा ताराचंद को दोषमुक्त किया है। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत ने इस मामले में चेक रिटर्न मेमो के साथ छेड़छाड़ करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बचाव पक्ष ने अदालत में यह तर्क दिया कि परिवादी से आरोपी ने कोई ऋण नहीं लिया परिवादी ने चैक का दुरुपयोग कर मामला पेश किया।

चेक रिटर्न मेमो के साथ छेड़छाड़ की गई है। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों को ध्यान से सुना। अदालत ने यह पाया कि परिवादी एक वैध ऋण के अस्तित्व को साबित करने में असफल रहा है। परिवादी ने न तो ऋण देने की कोई तारीख माह व वर्ष बताया और ना ही यह बताया कि उसने कितनी मूल राशि ऋण के रूप में दी। इसके अलावा अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि परिवादी ने खुद यह स्वीकार किया है कि वह पैसे ब्याज पर देने का काम नहीं करता तथा उसका मनी लॉन्ड्रिंग का लाइसेंस नहीं बना हुआ तथा उसे राशि दिए जाने का समय याद नहीं है।

इसके अतिरिक्त अदालत ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत चेक रिटर्न मैमो व चेक रिटर्न रजिस्टर में काट-छांट की गई होने से भी प्रकरण को विश्वसनीय नहीं माना। अदालत ने अपने फैसले में परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में भी कई विसंगतियां पाई, इसलिए अदालत ने अभियुक्त को बरी कर दिया व चेक रिटर्न मैमो व चेक रिटर्न रजिस्टर में चेक के अनादरण की दिनांक के साथ काट-छांट करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं ताराचंद की ओर से पैरवी अधिवक्ता योगेशचंद जैन ने की थी।

जीवन भर के सफर के लिए तैराकी का शुक्रिया। जब मैंने 2001 में स्प्रिंगफील्ड वाईएमसीए में शुरुआत की थी, तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए क्या-क्या होगा। – रयान हेल्ड

अमेरिकी तैराक, 30 साल की उम्र में प्रतिस्पधीरू तैराकी से संन्यास को लेकर बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी

नाओमी ओसाका

दुनिया की पूर्व नंबर-1 खिलाड़ी नाओमी ओसाका पूर्व वर्ल्ड नंबर 3एलीना स्वितोलिना को हराकर कनाडियन ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ओसाका ने इस दौरान स्वितोलिना को 6-2. 6-2 से हराकर डब्ल्यूटीए 1000 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाई है और टाइटल जीतने पर नंबर 21 तक जा सकती है। आखिरी बार 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में डब्ल्यूटीए टूर का खिताब जीतने वाली ओसाका ने 10वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के खिलाफ पांच में से चार ब्रेक प्वाइंट बचाए और क्वार्टर फाइनल मुकाबला सिर्फ एक घंटे आठ मिनट में जीत लिया।

क्या आप जानते हैं ?... मोहम्मद सिराज 23 विकेट लेकर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जसप्रीत बुमराह के भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी की।

गिल जुलाई महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामांकित

दुबई, 6 अगस्त। भारत के कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को आईसीसी महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर के साथ, भारत के कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुष वर्ग में नामांकित किया गया है। इंग्लैंड की खिलाड़ी सोफिया डंकले और सोफी एक्लेस्टोन के साथ आयरलैंड की कप्तान गैबी लुईस भी महिला वर्ग में नामांकित हैं। इस दौरान गिल ने कुल 567 रन बनाए हैं, जिसमें बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बनाए गए 430 रन भी शामिल हैं, जो उन्हें इस दौड़ में शामिल करता है। वहीं स्टोक्स और मुल्डर ने भी शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। डंकले के बल्ले और एक्लेस्टोन के भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर किए गए प्रदर्शन ने उन्हें इस दौड़ में शामिल किया है, जबकि लुईस

का जिम्बाब्वे के खिलाफ दोनों प्रारूपों में बल्ले से अच्छा प्रदर्शन उन्हें इस दौड़ में शामिल करता है। एक स्वतंत्र आईसीसी वोटिंग अकादमी और दुनिया भर के प्रशंसकों को अब विजेताओं का फैसला करने के लिए वोट देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

सिराज ने हाल के दिनों में बहुत सुधार किया है : मोईन अली

लंदन, 6 अगस्त। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोईन अली ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ संपन्न सीरीज़ में भारत के मोहम्मद सिराज के शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की और कहा कि इस गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक संपूर्ण गेंदबाज बनने की दिशा में बड़ी प्रगति की है। प्रमुख प्रॉपर्टी डेवलपर जीएफएस डेवलपमेंट्स के लंदन कार्यालय के हालिया दौरे के दौरान मोईन अली ने कहा, सिराज ने इंग्लैंड सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। गेंद के साथ उनकी ऊर्जा, आक्रामकता और निरंतरता विश्वस्तरीय है। वह भारत के लिए एक सच्चे मैच विजेता के रूप में परिपक्व हुए हैं और बल्लेबाजों के लिए उनका सामना करना हमेशा एक चुनौती होती है। उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात गेंद पर नियंत्रण रखने की उनकी क्षमता है। उनका दिल बड़ा है और वे कभी पीछे नहीं हटते – यही उन्हें इतना खास बनाता है। उनके द्वारा डाले जा रहे प्रभाव का श्रेय उन्हें जाता है, अली, जो वर्तमान में दुबई में रहते हैं और जीएफएस कार्यालय में अपनी यात्रा के दौरान वहाँ की संपत्तियों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ सभी पांच टेस्ट मैच खेले और कोई भी मैच नहीं छोड़ा। उन्होंने पांच टेस्ट मैचों में 23 विकेट लेकर श्रृंखला का अंत सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में किया। मोईन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और दुबई में अपनी क्रिकेट क्षमताओं को तलाश रहे हैं, जहां वे अब रहते हैं और इस शहर को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मानते हैं। सीएफएस डेवलपमेंट्स के सीईओ इरफान वाहिद ने कहा, मोईन एक बेहतरीन क्रिकेटर थे और उन्होंने हाल ही में हुए डब्ल्यूसीएल टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था। हमारे लंदन कार्यालय में मोईन अली का स्वागत करते हुए हमें खुशी हुई। वह न केवल एक विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं, बल्कि एक विचारशील व्यक्ति भी हैं। हम उन्हें उनकी पसंद और मूल्यों के अनुरूप संपत्ति खोजने में मदद करने के लिए उत्साहित हैं। मोईन अली हाल ही में संपन्न वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स में इंग्लैंड चैंपियंस के लिए खेले थे और आगामी टी20 टूर्नामेंट में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखना चाहेंगे।

हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है : मैकुलम

लंदन, 6 अगस्त। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का कहना है कि उन्होंने उन क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहां इंग्लैंड को एशेज से पहले सुधार करना होगा, जब भारत के खिलाफ एक रोमांचक सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई और मुख्य कोच का मानना है कि पांचवें टेस्ट में भारतीय टीम जीत की हकदार थी। भारत ने इस एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के 25वें और आखिरी दिन 56 मिनट के शानदार खेल में 2-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए छह रन की जीत हासिल की, जो रनों के लिहाज से उनकी सबसे कम अंतर की जीत थी।

मैकुलम ने कहा, इस टेस्ट में भारत जिस तरह से अंत तक खेला, मोहम्मद सिराज में अपने 30वें ओवर में 90 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदबाजी करने के लिए एक शेर का दिल दिखाया, जो उनके पांचवें टेस्ट मैच में एक अविश्वसनीय प्रयास था। इंग्लैंड अब सितंबर में दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ सफ़ेद गेंद की सीरीज में उतरेगा, इसलिए खिलाड़ियों के पास आराम करने का समय है। साल की शुरुआत से ही कोच के रूप में मैकुलम दोनों चुनौतियों में शामिल रहेंगे।

मैकुलम ने कहा, हम पहले सब कुछ शांत होने देंगे और हम यह पता लगाएंगे कि क्या अच्छा रहा है और फिर यह तय करना शुरू करेंगे कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं, ताकि जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचें, तो हमारे पास एक बड़ा मौक़ा हो। हम जानते हैं कि हमारे पास सुधार की कुछ गुंजाइश है। यह एक प्रतिस्पर्धी सीरीज रही है, जिसमें, कुछ खिलाड़ी चोटिल भी हुए। यह सीरीज़ ड्रॉ हो चुकी है।

बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जाएगा

नई दिल्ली, 6 अगस्त। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के आरटीआई संबंधी प्रावधान में संशोधन किया है जिसके तहत केवल उन्हीं संस्थाओं को इसके दायरे में रखा गया है जो सरकारी अनुदान और सहायता पर निर्भर हैं और इससे बीसीसीआई को काफी राहत मिली होगी। बीसीसीआई अब भी आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन किया है। इसके अनुसार, अब केवल उन्हीं खेल संगठनों को इसके दायरे में लाया गया है, जो सरकारी अनुदान और सहायता लेते हैं।

बीसीसीआई खेल मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं लेता है। हालांकि विभिन्न संगठन कई बार बीसीसीआई को आरटीआई (सूचना का अधिकार) के दायरे में लाने की मांग करते रहे हैं। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 जुलाई को लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025 पेश किया था। इस बिल में खेलों के विकास के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बॉडी, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, नेशनल खेल इलेक्शन पैनल और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाने के प्रावधान हैं। पिछले महीने लोकसभा में पेश बिल के क्लॉज 15(2) में कहा गया था कि किसी मान्यता प्राप्त खेल संगठन को इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा।

बदले गए प्रावधान में लिखा है कि सिर्फ वे संस्थाएं आरटीआई के दायरे में आएंगी, जो सरकार से फंड या मदद लेती हैं। अब सरकारी धन से चलने वाले संगठनों पर ही आरटीआई लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बीसीसीआई अब आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि सरकारी मदद सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। अगर किसी खेल संगठन को इवेंट कराने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर या कोई और सुविधा मिलती है, तो उसे भी आरटीआई के तहत लाया जा सकता है। बीसीसीआई को आरटीआई में लाने का सरकार पहले भी कर चुकी है प्रयास सरकार इससे पहले बीसीसीआई को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन बीसीसीआई के लिए यह हमेशा से पेचीदा मामला रहा है।

फुटबॉल कोच ने एसएमएस स्टेडियम में पत्रकार के साथ की धक्का-मुक्की

जयपुर, 6 अगस्त। फुटबॉल खिलाड़ियों के हाथों में फावड़े देकर फुटबाल ग्राउंड को ठीक करा रहे कोच को देखा तो रिपोर्टर फोटो खींचने लगा तभी पार्ट टाइम कोच नीत कमल ने पत्रकार के साथ धक्का मुक्की कर मोबाइल छीनने की कोशिश की। जब रिपोर्टर ने इसका विरोध किया तो कोच नीत कमल कहने लगा कि स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों ने फुटबॉल खिलाड़ियों को ही फुटबाल ग्राउंड ठीक करने को कहा है। ये कहकर फुटबाल कोच नीत कमल ने सभी खिलाड़ियों से वापस फावड़े फेंकने को कहा। खिलाड़ियों से फुटबाल ग्राउंड को ठीक कराना कहां तक जायज़ है ये तो खेल परिषद सचिव राजेन्द्र सिंह सिसौदिया और नीरज पवन ही बता सकते हैं।

पूर्व काउंटी कोच यौन दुराचार के आरोप में निलंबित

लंदन, 6 अगस्त। एक अज्ञात पूर्व काउंटी क्रिकेट कोच को यौन दुराचार के आरोप स्वीकार करने के बाद नौ महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। स्वतंत्र क्रिकेट अनुशासन पैनल ने पाया कि उस व्यक्ति ने 2023 और 2024 की गर्मियों में स्टाफ की दो महिला जूनियर सदस्यों को यौन रूप से स्पष्ट तस्वीरें भेजी थीं। उसने पेशेवर आचरण नियमों के पांच उल्लंघनों को स्वीकार किया, जिसमें दो सहकर्मियों को अनचाही यौन तस्वीरें भेजना भी शामिल है। पैनल ने असाधारण स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों और नाम सार्वजनिक करने पर गंभीर नुकसान के खतरे के कारण व्यक्ति की पहचान बताने से इनकार कर दिया। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी महिला प्रतिवादी से बहुत छोटी थी और वह क्रिकेट क्लब में उससे कहीं अधिक वरिष्ठ पद पर था। उसके व्यवहार के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया और तब से वह खेल में कार्यरत नहीं है।

पैनल को दिए गए आवेदनों में, यह उल्लेख किया गया कि कोच ने अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी है और सच्चा पश्चाताप व्यक्त किया है। बीबीसी की एक खबर के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने स्वेच्छा से एक शिक्षा पाठ्यक्रम लिया था और अवांछित स्पष्ट संदेशों के प्रभाव को समझने के लिए एक पूर्व पेशेवर खिलाड़ी के साथ काम किया था। रिपोर्ट में कहा गया है, उन्हें उम्मीद थी कि अब वह एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। उन्हें कार्यस्थल की सीमाओं, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और यौन उत्पीड़न के बारे में बेहतर समझ थी। यह प्रतिबंध आरोपों के दर्ज होने से छह महीने पहले लगाया गया है, साथ ही तीन महीने का निलंबन और एक अनिवार्य शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। क्रिकेट नियामक के प्रबंध निदेशक क्रिस हावर्ड ने कहा: इस तरह का आचरण अस्वीकार्य है। जहां ऐसे मामले सामने आते हैं, उनकी जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

राशिद खान की अगुवाई में अफगानिस्तान खेलेगा एशिया कप

काबुल, 6 अगस्त। स्टार लेग स्पिनर राशिद खान की अगुवाई में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आगामी एशिया कप में खेलेगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात में नौ से 28 सितंबर तक होने वाले एशिया कप के लिए 22 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। एसीबी की चयन समिति के सदस्य मीर मुबारिज ने बताया, राशिद खान अफगानिस्तान के सुपरस्टार हैं। उन्होंने हमेशा टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। फॉर्म में होना या खराब होना, यह खेल का हिस्सा है, लेकिन वह अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे मजबूती से वापसी करनी है और टीम और देश के लिए बड़े टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करना है।

मुबारिज ने कहा, हमने त्रिकोणीय सीरीज और एशिया कप से पहले तैयारी शिविर के लिए एक प्रारंभिक टीम की घोषणा कर दी है, जहां नए खिलाड़ियों की परख कोचिंग स्टाफ और कप्तान, दोनों प्रशिक्षण और तैयारी शिविर के दौरान करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर चोटों के कारण उन्हें अपनी योजना में बदलाव नहीं करना पड़ा, तो वे प्रारंभिक शिविर के 22 सदस्यों में से ही अपनी विश्व कप टीम का चयन करेंगे।

उन्होंने टीम में शामिल तेज गेंदबाजो को लेकर कहा, हां , हम शायद आगामी एशिया कप में इन्हीं 22 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे, लेकिन चोट लगने की स्थिति में बदलाव हो सकते हैं, और हम समय के साथ इन मुद्दों का ध्यान रखेंगे। हमने अब्दुल्ला अहमदजई, बशीर अहमद को टीम में शामिल किया है, और सलीम सफी भी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। इसलिए, वे सभी 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करने में सक्षम हैं।

उन्होंने कहा, पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान के पास राशिद खान, मुजीब, मोहम्मद नबी और अल्लाह मोहम्मद गजनफर जैसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं। हमने नांग्याल खारोटी और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले शराफुद्दीन अशरफ को भी टीम में शामिल किया है

आरसीए करौली जिला अंडर-19 डूंगरपुर शील्ड टीम की ओपन चयन ट्रायल 8 को

जयपुर, 6 अगस्त। आरसीए के तत्वाधान में आयोजित होने वाली आगामी राज्य स्तरीय अंडर 19 डूंगरपुर क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली करौली जिला क्रिकेट संघ टीम के चयन हेतु आरसीए द्वारा चयन ट्रायल आगामी 8 अगस्त को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित आरसीए अकादमी पर 10 बजे आयोजन किया जायेगा। राजस्थान क्रिकेट संघ एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत के अनुसार चयन ट्रायल में वो ही खिलाडी भाग ले सकते हैं जिनका जन्म दिनांक 1/9/2006 या उसके पश्चात हो। चयन ट्रायल में भाग लेने हेतु खिलाडियों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज साथ लाना आवश्यक है :- कंप्यूटर जनित जन्म प्रमाण पत्र (अनिवार्य), मूल प्रमाण पत्र (अनिवार्य), पिछले तीन वर्षों की शिक्षा की अंकतालिका (अनिवार्य), आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/पैन कार्ड।

जयपुर जिले की सीनियर गर्ल्स फुटबॉल टीम के चयन हेतु ट्रायल

जयपुर, 6 अगस्त। राजस्थान फुटबाल संघ और भीलवाड़ा जिला फुटबाल संघ के तत्वाधान में राजस्थान राज्य सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता भीलवाड़ा में 16 से 18 अगस्त के मध्य आयोजित की जा रही है। इसमें भाग लेने वाली जयपुर जिले की टीम के चयन हेतु ट्रायल का आयोजन आगामी 10 अगस्त, रविवार को एसएमएस स्कूल के फुटबॉल ठाउंड, रामबाग सर्किल, जयपुर में आयोजित की जा रही है। यह ट्रायल राजस्थान फुटबाल संघ के द्वारा गठित जयपुर जिला फुटबॉल संचालन समिति के द्वारा आयोजित की जा रही है। संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य अब्दुल जब्बार ने बताया कि जयपुर जिले की टीम की इस ट्रायल के लिए वह महिला खिलाडी जिनके आधार कार्ड जयपुर जिले का है यानी कि वह जयपुर जिले के निवासी है वही पात्र है। सभी इच्छुक खिलाडियों को रविवार 10 अगस्त को सुबह 7 बजे तक एसएमएस स्कूल के फुटबॉल ठाउंड पर ट्रायल हेतु रिपोर्ट करनी है। ट्रायल में भाग लेने हेतु सभी इच्छुक खिलाडियों को 9 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।

भारतीय एथलीट विश्व खेल 2025 के पांच खेलों की 23 पदक स्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा

चेंगदू (चीन), 6 अगस्त। भारतीय एथलीटों की 17 सदस्यीय टीम आज से शुरु हो रहे विश्व खेल 2025 के 12वें संस्करण की पांच खेलों की 23 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेगी। इस बार विश्व खेलों में 34 खेलों और 60 विधाओं में 253 पदक स्पर्धाएं होंगी। पॉवरबोटिंग और चीयरलीडिंग को पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। भारत इनमें से कुल पांच खेलों तीरंदाजी, बिलियर्ड्स, रैकेटबॉल, रोलर स्पोर्ट्स या स्केटिंग और वुशु में 23 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। भारत के तीरंदाजी दल में अभिषेक वर्मा और परनीत कौर, स्पीडस्केटर वेलकुमार आनंद कुमार और आर्यनपाल सिंह घुमन, तथा वुशु एथलीट नाओरेम रोशिबिना देवी, मधुरा धमनगांवकर शामिल हैं। भारत मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में भी भाग लेगा, जो कि लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 में भी शामिल होगी।

भारत की तनवी महिला वर्ग के सेमीफाइनल में

यासिन पुरुष और नूर महिला वर्ग के सेमीफाइनल में

जयपुर, 6 अगस्त। भारत की स्टार स्क्वैश खिलाड़ी तनवी खन्ना ने बुधवार को यहां बड़ा उलट फेर करते हुए सवाई मानसिंह स्टेडियम के स्क्वैश कोर्ट्स पर खेली जा रही एचसीएल इंडिया टूर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। तनवी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिस्त्र की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी मेन्ना वालिद को पांच सेटों तक चले कड़े संघर्ष में 3-2 से पराजित कर दिया। भारतीय खिलाड़ी ने 54 मिनट तक चला यह मुकाबला 11-8, 8-11, 11-7, 10-12, 11-6 से जीता। सेमीफाइनल में तन्वी खन्ना का मुकाबला मलेशिया की गोह जी झुआन से होगा।

आज का एक और बड़ा उलटफेर पुरुष वर्ग में दिखा जहां गैर वरीयता के मिस्त्र के सैफ रेफे ने मलेशिया के चौथी वरीयता के डेरेन प्रगासस को पांच सेटों तक चले कड़े संघर्ष में 11-3, 5-11, 11-13, 11-2, 11-3 से हरा सेमी फाइनल में जगह बना ली। ये मुकाबला 64 मिनट तक चला। पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त मिस्त्र के यासिन शोहदी नूर खफागी आसान जीत के साथ अंतिम चार में पहुंच गए। पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड यासिन शोहदी ने जापान के नाओकी हयाशी को आसानी से 11-2, 11-6, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं तीसरी वरीयता के श्रीलंका के रविन्दु लस्किरी ने मिस्त्र के करीम अगिब को चार सेटों में 11-4, 11-7, 7-11, 11-5 से हरा सेमी फाइनल में कदम रखा।

महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता की मिस्त्र की नूर खफागी ने भारत की पूजा आरती रघु के 11-3, 11-3, 11-5 से हरा अंतिम चार में जगह बनाई। वहीं अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जापान की अकारी मिडोरिकावा ने भारत की शमीना रियाज को मात्र 21 मिनट में ही 13-11, 11-6, 11-5 से हरा सेमी फाइनल में जगह पक्की कर ली। मलेशिया की गोह झी शुआन ने भी भारत की छठी वरीयता की अंजली सेमवाल को 11-3, 8-11, 11-5, 11-5 से हरा सेमी फाइनल में प्रवेश कर लिया।

ओजिक्यू के सहयोग द्वारा कोचेज सेमिनार में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया

जयपुर, 6 अगस्त। भारतीय तीरंदाजी संघ व राजस्थान तीरंदाजी संघ द्वारा ओजिक्यू के सहयोग से जयपुर में चल रही तीन दिवसीय कोचेज सेमिनार का आयोजन चल रहा है। यह सेमिनार जयपुर के एक प्रमुख होटल में आयोजित हो रहा है, जिसमें चयनित 45 प्रशिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य प्रशिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित करना और देश में तीरंदाजी की कोचिंग संरचना को सशक्त बनाना है। सेमिनार मे आज ओजिक्यू के सचिन ने सटैन्थ और कन्डीनसिग की जानकारी दी। वहीं सभी कोचों को आज प्रैक्टिकल के साथ प्रशिक्षण दिया एवं नवीन वदलाव नियमो की जानकारी के साथ डोपिंग से खिलाड़ियों को वचाने की महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने आज सभी कोचों का स्वागत किया।

राज्य स्तरीय अंडर-19 वीमेन ट्रायल के पहले दिन राज्य की 450 खिलाड़ी पहुंचे

जयपुर, 6 अगस्त। राजस्थान क्रिकेट संघ एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत के अनुसार राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आज से जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम स्थित अकादमी पर आयोजित की जा रहे 3 दिवसीय अंडर 19 वीमेन चयन ट्रायल के पहले दिन समस्त राज्य से लगभग 450 महिला खिलाडियों ने चयन ट्रायल में भाग लेने रजिस्ट्रेशन कराया। संयोजक के अनुसार आरसीए महिला चयन कमेटी ने आज चयन ट्रायल के पहले दिन लगभग 270 महिला खिलाडियों के प्रदर्शन व प्रतिभा को दौरान देखा। कल दिनांक 7 अगस्त को चयन ट्रायल के दूसरे दिन शेष महिला खिलाडियों की चयन ट्रायल होगी। आज सुबह आरसीए द्वारा आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय अंडर 19 वीमेन चयन ट्रायल के अवसर पर आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत ने आरसीए अकादमी पहुंच राज्य की युवा महिला खिलाडियों की चयन ट्रायल की पूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण किया। साथ ही खिलाडियों से चर्चा करते हुए उन्हें आरसीए द्वारा हर स्तर पर उच्च स्तरीय पूर्ण पारदर्शी खेल वातावरण व सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। इस दौरान संयोजक डी डी कुमावत ने राज्य के हर कोने से आयी हुई राज्य की युवा महिला खिलाडियों व उनके परिजनों के लिए चयन ट्रायल के दौरान सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करने के लिए आरसीए स्टाफ को विशेष निर्देश भी दिए।

राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन की घटिया निर्माण कार्य की वजह से ही हमने लेजेंजी टी-10 लीग के आयोजकों को साउथ पवेलियन की इजाजत नहीं दी गई

दोबारा से फोर्सिलिंग नई लगाकर साउथ पवेलियन की दीवारों की कमी को छुपाया नहीं जा सकता : नीरज के. पवन

जयपुर, 6 अगस्त। साउथ ब्लॉक में आ रही समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन द्वारा इस पूरे मामले में जिस तरह की लापरवाही की गई है उस निर्माण कार्य को जब तक सुरक्षित रूप में नहीं किया जाएगा तब तक कार्य समाप्त नहीं माना जाएगा। स्टेडियम में साउथ ब्लॉक पहली बारिश ही नहीं झेल पाया है। जिससे सरकार के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए है।

ग्राउंड फ्लोर पर बने हॉल और दोनों ड्रेसिंग रूम में डक्टिंग के माध्यम से पानी फर्श पर भर रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर बने हॉल की फॉल सीलिंग गिर चुकी है। उस पर लगी सभी लाइट्स लटक गई है। वुडन फ्लोरिंग भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जयपुर में डोमेस्टिक टूर्नामेंट के

अलावा प्राइवेट टूर्नामेंट आयोजित किये जाएंगे अगर ऐसी स्थिति में किसी टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो खिलाड़ियों ओर उनके साथ आए मेहमानों, दर्शकों की जान मुश्किल में आ सकती है। कोई भी दुर्घटना साउथ पवेलियन में कभी भी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ दुबारा से फोर्सिलिंग नए लगा कर साउथ पवेलियन की दीवारों की कमी को छुपाया नहीं जा सकता।

राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन की घटिया निर्माण कार्य की वजह से ही हमने लेजेंजी

टी10 लीग के आयोजकों को साउथ पवेलियन की इजाजत नहीं दी है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो पाए इसीलिए साउथ पवेलियन में किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों, दर्शकों के साथ साथ कैमरामैन, ऑफिस स्टाफ की सुरक्षा जरूरी है। साउथ पवेलियन की दीवारें अपनी बर्बादी की कहानी खुद तस्वीरों से बयां करती नजर आ रही है। ईंटों की चुनाई करके उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। बिल्डिंग का वजन सहने के लिए बिना प्लास्टर किए ही लीपापोती कर दी गई।

हाइजिया वेंचर्स ने अपनी टीम के लिए सानिया मिर्जा को बनाया ब्रांड एंबेसडर

नई दिल्ली, 6 अगस्त। गौरव अग्रवाल की कनाडा समर्थित निवेश फर्म हाइजिया वेंचर्स ने टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) के सातवें सीजन से पहले गुरुग्राम ग्रैंड स्लैमर्स टीम को खरीदने के साथ ही दिग्गज स्टार सानिया मिर्जा को टीम का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। टीपीएल भारत की चौथी ऐसी स्पोर्ट्स लीग बन गई है जो लगातार सातवें सीजन में पहुंची है। इसकी फास्ट-पेस्ड और दर्शकों को पसंद आने वाली प्रारूप की वजह से ये लीग लगातार निवेशकों और दर्शकों को आकर्षित कर रही है। गौरव अग्रवाल कहा, टेनिस और खेलों से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है। एक पिता के तौर पर भी मैं युवा टेनिस खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहता हूं। यह निवेश खेल और फ्रेंचाइज़ी मैनेजमेंट में हमारे कदम को मजबूत करता है। सानिया मिर्जा ने कहा, मैं एक ऐसी टीम से जुड़कर खुश हूं जो टैलेंट और इनोवेशन दोनों को महत्व देती है।

माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने के लिए डीपीआर बनेगी

सात हजार करोड़ रूपए की परियोजना से पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर की पेयजल समस्या का स्थाई निदान होगा

जयपुर, 6 अगस्त। पाली, जालोर, सिरोही बाड़मेर में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब मूर्त रूप लेगा। इस विषय को लेकर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में सात हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के संबंध में चर्चा हुई।

- मुख्यमंत्री भजनलाल, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने परियोजना के बारे में विस्तार से ब्रीफ किया।
- वाप्कोस ने परियोजना की इन्सपैक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग को सौंपी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बुधवार को सुमेरपुर विधायक व केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने एक बैठक में माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाले सात हज़ार करोड़ रूपए के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा की।

बैठक के बाद केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माही एवं सोम नदी का मानसून अवधि का अधिशेष जल, जयसमंद बांध सहित अन्य बांधों को भरते हुए जवाई बांध तक लाने संबंधी कार्य की, 2024-25 के बजट में घोषणा की थी। इस परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए 15.60 करोड़ रुपए की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जल संसाधान विभाग, जयपुर के मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। इस कार्य के लिए अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खंड सलूंबर ने वाप्कोस लिमिटेड से अनुबंध कर कार्यादेश भी जारी कर दिए। इसके बाद वाप्कोस द्वारा इन्सपेक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग, उदयपुर को प्रस्तुत किये जाने के बाद विभाग ने उसका अनुमोदन भी कर दिया है।

केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सात हजार करोड़ रुपए का यह महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा होने पर उदयपुर, सिरोही, पाली एवं जोधपुर जिले में पेयजल संबंधी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही, 16 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का पुर्नस्थापन होगा।

सीजेआई गवई का सीनियर वकीलों को अल्टीमेटम

नई दिल्ली, 06 अगस्त। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी आर गवई ने बुधवार, 6 अगस्त 2025 को साफ कर दिया कि 11 अगस्त से कोई भी सीनियर वकील उनकी अदालत में तत्काल सुनवाई के लिए मामले नहीं ला सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका मिल सके।

सीजेआई गवई ने वकीलों की ओर से तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई

- गवई ने कहा, 11 अगस्त से मेरे कोर्ट में कोई भी सीनियर वकील तत्काल सुनवाई के लिए केस नहीं ला सकेगा।

के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख करने की प्रथा को दोबारा शुरू कर दिया था, जिसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बंद कर दिया था।

सीजेआई गवई ने कहा, "इस बात की पुरजोर मांग उठ रही है कि सीनियर वकीलों को किसी भी मामले में तत्काल सुनवाई के लिए मेंशन न किया जाए।"

उन्होंने अदालत के कर्मचारियों से कहा कि वे एक नोटिस जारी करें कि सोमवार से उनकी अदालत में किसी भी वरिष्ठ वकील को तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई के लिए मामलों का लाने की इजाजत नहीं होगी।

सीजेआई ने कहा सोमवार से किसी भी सीनियर वकील, किसी भी नामित सीनियर वकील को मामलों का उल्लेख करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका दिया जाना चाहिए।

मैडिकल बोर्ड में 29 में से 24 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगिरी के लिए अनफिट निकले

जयपुर, 6 अगस्त । एसओजी ने सरकारी नौकरी में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एसओजी पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से सूचना मिली कि विगत समय से विभिन्न सरकारी नौकरियों में अनेक चयनित उम्मीदवारों ने दिव्यांग नहीं होते हुए भी फर्जी तरीके से बनवाया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है।

- एसओजी ने दिव्यांगत प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी पाने के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया।
- सबसे ज्यादा अनफिट कर्मचारी श्रव्य बाधित श्रेणी में पाए गए।

सूचना मिलने के बाद एसओजी अतिरक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा के नेतृत्व में जांच दल गठित कर एसएमएस मैडिकल कॉलेज के विभिन्न विशेषज्ञों का बोर्ड गठित करवा कर दिव्यांग श्रेणी के लोक सेवकों की पुन: मैडिकल जांच करवाई गई, जिसमें 29 दिव्यांग लोक सेवकों की मैडिकल जांच कि रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें से मात्र 5 लोक सेवकों में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना पाया गया और बाकी 24 तथाकथित दिव्यांगों को मैडिकल बोर्ड ने दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट बताया। श्रव्यबाधित 13 में से 13 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए। दृष्टिबाधित कथाकथित 8 दिव्यांग में से 6 दिव्यांग कैटेगरी के नहीं पाए गए। इसी तरह लोकोमोटर एवं अन्य प्रकार के 8 लोक सेवकों में से 5 दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए।

अनफिट पाए गए लोक सेवक हैं- महेन्द्र पाल पुत्र गिरधारी सिंह, तहसील पुलिस थाना भीम राजसमंद; सवाई सिंह गुर्जर टिगरिया का पुरा, हिण्डौन, करौली; हन्दु गुर्जर चंदवाजी जयपुर; मनीष कुमार कटारा बरौली, रुपवास, भरतपुर; केशव उर्फ खुब्बाराम रेनवाल; कविता रेनवाल; बिकेश कुमार नदबई, भरतपुर; भानुप्रताप कटारा, रुपवास; नफीस जुरहरा, भरतपुर; रणजीत सिंह बयाना, भरतपुर; कलुआ राम बयाना भरतपुर; पवन कुमार आबूरोड सिरोही; विनोद कंवर आबू रोड सिरोही; दिनेश कुमार, धौरीमन्ना बाड़मेर; लोकेश नदबई भरतपुर; संजय नोखा बीकानेर; दीपू डीडवाना, कुचामन; गेपू बलूपुरा पाली; प्रशांत सिंह गांधी नगर सिरोही; छिन्द्रपाल सिंह केसरीसिंहपुरा गंगानगर; आसी कुमारी मारुडी, बाड़मेर; डॉ शंकर लाल मीणा देवपुरा बूंदी; जगदीश चौधरी रुपनगढ जिला अजमेर; किशोर सिंह सबलपुर डीडवाना कुचामन।

एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक बयान में बताया कि 1 अक्टूबर से एयर इंडिया के सभी इंटरनेशनल फ्लाइटों की आवाजाही पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक अक्टूबर से एयर इंडिया के इंटरनेशनल विमानों की आवाजाही 12 जून से पहले वाली स्थिति में आ जाएगी।

अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया के, इंटरनेशनल के साथ-साथ, घरेलू विमानों की उड़ानों पर भी असर पड़ा था। दुर्घटना के बाद, एयर इंडिया ने सुरक्षा जांच लंबित रहने तक अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आंशिक रूप से रोक दिया था।

समुद्री माल परिवहन बिल पर संसद की मुहर

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। भारत से शेष दुनिया के समुद्री बंदगाहों तक माल ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों और अधिकार तथा छूट से संबंधित प्रावधानों वाले समुद्री माल परिवहन विधेयक को बुधवार को राज्य सभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच पारित कर दिया। इसके साथ ही, इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गयी। इस विधेयक को लोक सभा ने गत 28 मार्च को पारित किया था।

राज्य सभा में आज शून्यकाल के दौरान पहले स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे कार्यवाही पुन: शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच पीठासीन उपसभापति भुवनेश्वर कलिता की अनुमति से मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चल रहे मणिपुर के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्यय का ब्योरा रखा। हंगामे के बीच ही, विधायी कार्य के एजेंडा में पहले स्थान पर उल्लिखित समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पर चर्चा करायी गयी। इस विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के कतिपय संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज करने के बाद, विधेयक को ध्वनिमत से अनुमोदित कर दिया गया।

विपक्ष ने संसदीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन झूठे दावों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है, जो संसद को सुचारू रूप से चलने से रोक रहे हैं।"

गोगोई ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि 1961 में राज्यसभा में चुनाव आचार संहिता के नियमों में संशोधन पर बहस हुई थी, उस चर्चा का नेतृत्व उस समय के कानून मंत्री गोपाल स्वरूप पाठक ने किया था।

गोगोई ने बताया कि 1981 में, कांग्रेस सांसद मनुभाई पटेल ने चुनावी कानूनों की समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा था।

कांग्रेस सांसद ने कहा, "1991 में, राज्यसभा में मौजूदा चुनावी कानूनों में संशोधन की तत्काल आवश्यकता पर बहस हुई। 2015 में, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के लिए प्रॉक्सी और ई-पोस्टल वोटिंग पर "कॉलिंग अटेंशन मोशन" प्रस्तुत किया था। कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने विपक्ष की राय को मानने की बात स्वीकार की।"

गोगोई ने कहा कि हाल ही में, 2019 में भी चुनावी सुधारों पर "अल्पकालिक चर्चा" हुई थी, जिसमें तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाग लिया था। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। सरकार को इस लंबे समय से लंबित और आवश्यक बहस में देरी नहीं करनी चाहिए।

गोगोई ने कहा, "आइए, संसद में चुनावी सुधारों पर चर्चा करें।"

रमेश ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि 1986 में भी व्यापक चुनावी सुधारों की आवश्यकता और संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने पर चर्चा हुई थी।

हाई कोर्ट के आदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यहां तक कि जब इस रिपोर्टर की खबर को कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वेबसाइट पर कुछ जूनियर स्टाफ द्वारा डाला गया, तो उसे कुछ ही मिनटों में हटा दिया गया। क्या पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की इसमें राजीव दत्ता के साथ कोई मिलीभगत है?

यह खबर हटाने का निर्देश देने के पीछे आखिर उनकी रूचि का क्या कारण था?

इसके अलावा, हैरानी की बात यह भी है कि कोटा या राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता ने, दिल्ली, जयपुर और कोटा में सत्ता के गलियारों में जो चल रहा है, उस पर कुछ भी नहीं कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू की "विद यू स्टालिन" योजना को हरी झंडी दी

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की "विद यू स्टालिन" योजना में वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नाम के इस्तेमाल पर रोक वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को रद्द दिया।

इसके साथ ही अदालत ने सरकारी योजना के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले अन्नाद्रमुक सांसद सी.वी. षणमुगम पर अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए, उसके खिलाफ राज्य सरकार और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) पार्टी की अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा, हमने बार-बार कहा है कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। अदालतों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक हिसाब-किताब निपटाने के लिए किया जाना चाहिए। इस आदेश के साथ ही शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की विद यू स्टालिन योजना हरी झंडी दे दी।

'अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए राज्य सरकारें चार हफ्ते में अधिसूचनाएं जारी करें'

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे अनाथ, कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे के तहत मुफ्त शिक्षा देने की अनुमति संबंधी अधिसूचनाएं चार सप्ताह के अंदर जारी करें।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और

- सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को, कमजोर वर्गों को शिक्षा के लिए दिए गए 25 प्रतिशत कोटा में शामिल करने के निर्देश दिए

न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने अधिवक्ता पौलोमी पाविनी शुक्ला की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा, दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात ने पहले ही अनाथ बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की परिभाषा में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बाकी राज्य भी इस संबंध में प्रक्रिया चार सप्ताह के भीतर पूरी कर लें। शीर्ष अदालत ने राज्यों को उन अनाथ बच्चों का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दियाद्ध जिन्हें स्कूलों में प्रवेश दिया गया है और जिन्हें दाखिले से मना कर दिया गया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संबंधित सर्वेक्षण में दाखिले से इनकार करने के कारण दर्ज किये जाएं।

उत्तरकाशी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के जगह-जगह अवरुद्ध हो जाने के कारण अनेक वाहन अब भी रास्ते में फंसे हुए हैं। हर्षिल स्थित सेना के कैंप में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिससे क्षेत्र में लॉजिस्टिक चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं। जैसे-जैसे खोज और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है, स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि मृतकों के आँकड़े में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और कई गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। उत्तरकाशी इस समय हाल के वर्षों की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है।

'वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्यौरा शनिवार तक पेश करें'

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिए

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह विशेष पुनरीक्षण के दौरान बिहार मतदाता सूची से हटाये गए 65 लाख लोगों (मृत और स्थायी पलायन करने वाले) का विवरण शनिवार तक दे।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुयान और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण की गुहार पर यह निर्देश दिया।

पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा, शनिवार तक जवाब दाखिल करें और भूषण को इसे देखने दें। फिर हम देख पाएंगे कि क्या खुलासा हुआ है और क्या नहीं।

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी जाएगी।

इस पर चुनाव आयोग के

- चुनाव आयोग ने कहा कि राजनैतिक दलों को यह जानकारी दी गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन दलों की लिस्ट मांगी जिन्हें यह जानकारी दी गई है।

अधिवक्ता ने कहा कि वह प्रस्तुत करेगा कि यह जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जानकारी साझा की गई है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि वह अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखे।

पीठ ने निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता से कहा, उन राजनीतिक दलों की सूची दीजिए, जिन्हें यह जानकारी दी गई है। हम 12 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। तब तक अपना (निर्वाचन आयोग का) जवाब दाखिल करें।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की चिंताओं पर कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी मिले।

एडीआर ने अपने आवेदन में कहा कि 25 जुलाई को निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया था कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

भूषण ने पीठ के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा, ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख नामों के छूटने की बात कही गई है, लेकिन इन नामों की कोई सूची नहीं दी गई। इसमें 32 लाख लोगों के पलायन की बात कही गई, लेकिन कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, उन्हें (चुनाव आयोग) यह बताना चाहिए कि 65 लाख लोग कौन हैं? कौन पलायन कर गए हैं। कौन मर गए हैं? जाहिर है, बीएलओ ने उस व्यक्ति को हटाने या न हटाने की सिफ़ारिश की है। भूषण ने दलील दी थी कि चुनाव आयोग ने दो निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। अन्य क्षेत्रों का क्या हुआ?

ट्रंप ने भारत पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की धमकियों के आगे झुकने से दृढ़ता से इनकार कर दिया है।

"इस बात को स्वीकार करो या नहीं", भारत अब दुनिया की प्रमुख भू-राजनीतिक शक्तियों के क्लब में आ गया है और इस पोज़ीशन के लिए कीमत तो भारत को चुकानी ही पड़ेगी। जब भारतीय निर्यात अमेरिकी बाजारों से बाहर हो जाएंगे, तो भारत को दूसरे बाजार तलाशने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

जहाँ एक तरफ भारत के अडिग रुख और अस्थिर स्वभाव वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे झुकने से इन्कार करने की कुछ हल्की सराहना जरूर हो रही है, वहीं, प्रतिक्रियाएं कुछ दबी-दबी हैं, सिवाय व्यापार और भू-राजनीति के, जो अब पूरी तरह एक-दूसरे से जुड़ चुके हैं।

ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस समय मॉस्को में पुतिन से बातचीत कर रहे हैं और मंगलवार को दोनों की मुलाकात को क्रेमलिन के प्रवक्ता ने "रचनात्मक" बताया है। भारत, ट्रंप की रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का पहला "भू-राजनीतिक शिकार" बन गया है। भारत की स्थिति यह हो गई है कि वह अब रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता, ऐसा करना बहुत अधिक झुकना होगा और भारत के अपने हितों को नुकसान पहुंचेगा।

अमेरिका को होने वाले निर्यात में कुछ असर पड़ने की तुलना में, तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूंढना भारत के लिए कहीं ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आखिरकार, अमेरिकी निर्यात भारत की समग्र अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा हिस्सा है और भारत की अर्थव्यवस्था उतनी निर्यात-निर्भर नहीं है, जितनी कुछ अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं।

इस अतिरिक्त टैरिफ के बारे में पहले से ही अनुमान था, लेकिन खास बात यह रही कि ट्रंप ने चीन पर ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया, जिससे एक बार फिर उनकी "टी.ए.सी.ओ." (ट्रंप ऑलवेज़ चिकन्स आउट) अर्थात् ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं, वाली छवि चरितार्थ होती हैं। चीन ने बहुत चतुराई से सेकन्डरी प्रतिबंधों से बचाव कर लिया, क्योंकि वह इस समय अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में शामिल है। यह बात तर्क से परे है, क्योंकि चीन तो रूस के युद्ध का कहीं अधिक मुखर और प्रभावी समर्थक रहा है।

महेश जोशी की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए 8 अगस्त का समय दिया है।

'जैसलमेर को तो मुगल भी नहीं जीत पाए थे'

जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने एन.सी.ई.आर.टी के नक्शे में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का अंग बताने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की

जैसलमेर, 06 अगस्त। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान विषयक पाठ्यपुस्तक में राजस्थान में जैसलमेर को तत्कालीन मराठा साम्राज्य के मानचित्र में दर्शाए जाने को लेकर जैसलमेर राजपरिवार के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है।

- एन.सी.ई.आर.टी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में पेज क्रमांक 7 पर छपे इस नक्शे में जैसलमेर, बूंदी, मेवाड़ व पंजाब को मराठा साम्राज्य के अधीन बताया गया है।
- मेवाड़ राजघराने के सदस्य व भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, बूंदी राजघराने के ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा, यह हमारे पूर्वजों के बलिदान को धूमिल करने की कोशिश है।

सिंह ने इसे ऐतिहासिक रूप से भ्रामक, तथ्यहीन और गंभीर त्रुटि करार देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इसमें तत्काल संशोधन करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों, राजकीय अभिलेखों एवं अन्य प्रामाणिक स्त्रोतों में जैसलमेर में मराठा साम्राज्य के किसी प्रकार के प्रभुत्व, कराधान, आक्रमण या हस्तक्षेप का कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, राजकीय पुस्तकों में भी स्पष्ट उल्लेखित है कि जैसलमेर रियासत में मराठाओं का कभी भी, कोई दखल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी जैसी शीर्ष शैक्षणिक संस्था द्वारा इस प्रकार की ऐतिहासिक त्रुटि करना, उसकी विश्वसनीयता और अकादमिक गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है।

सिंह ने कहा कि यह विषय केवल एक मानचित्र की गलती नहीं, बल्कि जैसलमेर की ऐतिहासिक गरिमा, सांस्कृतिक अस्मिता और विद्यार्थियों को दिये जाने वाले ज्ञान की सत्यता से जुड़ा विषय है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस मानचित्र के संबंध में हस्तक्षेप करने की मांग की।

राज परिवार के विक्रम सिंह ने बताया कि जैसलमेर के दर्ज इतिहास के अनुसार- मुगल भी जैसलमेर को नहीं जीत पाये थे। जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में साल 1176 के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल-जैसल ने की थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहां भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंश क्रम को भंग किए हुए 770 वर्ष तक सतत शासन किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसलमेर राज्य ने भारत के इतिहास के कई काल खण्डों को देखा एवं सहा है। यह राज्य मुगल साम्राज्य में भी लगभग 300 वर्षों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा।

जैसलमेर शहर पर खिलजी, राठौर, मुगल, तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया था, लेकिन वे कभी इसे जीत नहीं पाए। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से लेकर समाप्ति तक भी इस राज्य ने अपने वंश गौरव एवं महत्व को यथावत रखा। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य और भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, उनकी पत्नी एवं राजसमंद से भाजपा सांसद महिमा कुमारी, बूंदी के पूर्व राजघराने के सदस्य ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा ने एनसीईआरटी के शिक्षाविदों पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह पूर्वजों के बलिदान को धूमिल करने का प्रयास है।

उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी के इस नक्शे में जैसलमेर, बूंदी, मेवाड़, पंजाब सहित देश के कई हिस्सों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है। यह नक्शा एनसीईआरटी की आठवीं की सामाजिक विज्ञान की किताब इकाई-तीन में पेज नंबर 71 पर छपा है। इस नक्शे पर पूर्व राजघरानों ने आपत्ति दर्ज कराई है।

एस.सी.ओ. सम्मेलन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की आवश्यकता के साथ संतुलित करना, भारत-चीन संबंधों की परिपक्वता की परीक्षा होगी। भारत के लिए यह यात्रा चीन की पाकिस्तान नीति पर असंतोष जताने के साथ-साथ व्यापार, तकनीक और बहुध्रुवीय वैश्विक शासन पर साझा सोच तलाशने के लिए भी होगी।

मोदी की चीन यात्रा भारत की व्यापक विदेश नीति में एक पुनर्मूल्यांकन का प्रतीक है, जो एक ध्रुवीकृत होते जा रहे विश्व में रणनीतिक लचीलापन बनाए रखने की कोशिश को दर्शाता है। वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच यह संतुलन भारत की अगली कूटनीतिक दिशा को परिभाषित कर सकता है।

इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के साथ बातचीत में आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दे शामिल रहने की संभावना है। भारत-चीन संबंधों में स्थिरता और संवाद बहाल करने की कोशिशें की जाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं।

अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा तनाव कम करने के प्रयास तेज़ हुए थे और कैलाश-मानसरोवर यात्रा की बहाली ने संबंधों को काफी हद तक सामान्य बनाने में मदद की थी।

2001 में स्थापित एससीओ का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को सहयोग के माध्यम से बढ़ावा देना है। इस समूह के वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं- बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान।

प्र.मंत्री ने कर्तव्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होंगे।

कर्तव्य भवन में पानी की ज़रूरतों के एक बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल के उपचार और पुन: उपयोग की व्यवस्था की गयी है। यह भवन 30 प्रतिशत कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें इमारत को ठंडा रखने और बाहरी शोर को कम करने के लिए विशेष कांच की खिड़कियाँ हैं। ऊर्जा-बचत करने वाली एलईडी लाइटें, ज़रूरत न होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्टें और बिजली के उपयोग को प्रबंधित करने की एक उन्नत प्रणाली है। कर्तव्य भवन-3 की छत पर लगे सौर पैनल हर साल 5 लाख 34 हजार यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा करेंगे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600